नई दिल्ली
गुरुवार
12 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 69
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



छठ घाटों के निरीक्षण में गायब मिले अधिकारी...पेज-05

DELHIN/2014/58158

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से...पेज-08

एक नजर

पंजाब में पीआरटीसी बस पुल से नीचे गिरी, 3 यात्रियों की मौत, 26 घायल

संगरूर। पंजाब के संगरूर जिले में बुधवार तड़के संगरूर से चंडीगढ़ जा रही यात्री पीआरटीसी बस अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकराने के बाद नीचे खेतों में गिर गई। इस हादसे में दो महिलाओं सहित तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। इनमें से 15 गंभीर घायलों को पटियाला के राजिंदरा अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस सुबह करीब 4 बजकर 40 मिनट पर संगरूर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। मस्तुआना साहिब के नजदीक पहुंचने पर चालक बस से नियंत्रण खो बैठा। बस पहले पुल की दीवार से टकराई और फिर नीचे उतरकर खेतों में पलट गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। संगरूर के पुलिस उपाधीक्षक दलबीर सिंह संधू के अनुसार बस निर्धारित समय से करीब दस मिनट देरी से चल रही थी। चालक समय की भरपाई करने के लिए तेज रफ्तार से बस चला रहा था। मृतकों में धूरी की दो महिलाएं और गांव थलेस निवासी 55 वर्षीय मंजीत सिंह शामिल हैं। पुलिस ने घायल छात्र विनय कुमार के बयान पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने प्रशासन को सभी घायलों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नौसेना के युद्धपोत बेतवा की मरम्मत 500 करोड़ रुपये से होगी, युद्धक क्षमता बढ़ेगी

नई दिल्ली,एजेंसी। पिछले एक दशक में कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस बेतवा की मरम्मत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में कराई जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में 498.58 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मपुत्र श्रेणी के इस युद्धपोत की प्रणोदन प्रणाली में व्यापक बदलाव किया जाएगा। मरम्मत के बाद आधुनिक हथियार प्रणाली के माध्यम से पोत की युद्धक क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना से जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव से जुड़े स्वदेशी औद्योगिक तंत्र की क्षमताएं और सुदृढ़ होंगी। विशेष रूप से इससे जटिल प्रणोदन प्रणाली में बदलाव तथा नौसैनिक प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में देश की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना में 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी होने की उम्मीद है। साथ ही भारतीय जहाज निर्माण उद्योग और उससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के विजन को नई गति प्रदान करेगी तथा देश की स्वदेशी नौसैनिक पोत मरम्मत एवं रखरखाव क्षमताओं को और मजबूत करेगी। इजराइल-लेबनान संघर्ष शुरू होने के समय 2006 में बेतवा युद्धपोत टास्क फोर्स 54 का हिस्सा था, जो भूमध्य सागर से लौट रहा था। ऑपरेशन सुकून के एक हिस्से के रूप में बेतवा ने लेबनान से साइप्रस तक भारतीय नागरिकों को निकालने में भाग लिया। उसके बाद यह जहाज कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हुआ।

भारत की राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए

स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों की सुंदर स्थिति का प्रश्न नहीं है; यह हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का भी परिचायक है: राष्ट्रपति



नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि किसी एक संस्था के अकेले के प्रयासों से स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हर नागरिक, हर घर, हर समुदाय और हर शहर की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों की सुंदर स्थिति का प्रश्न नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व का भी परिचायक है। यह हमारे घरेलू व्यवहार एवं आदतों का भी द्योतक होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि हर नागरिक को, विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और सामुदायिक संगठनों को, स्वच्छता से जुड़े विभिन्न पहलुओं से जुड़ना चाहिए। उन्हें अपने अनुभवों के साथ ही उन कमियों को भी रिपोर्ट करना चाहिए जिनके समाधान हमारे शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे नगर प्रशासन और नागरिकों के बीच निरंतर संवाद को बढ़ावा मिलेगा और आपसी विश्वास, पारदर्शिता तथा जवाबदेही मजबूत होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि अपने आस-पास के इलाकों की स्वच्छता को परखने के लिए नागरिक ही सबसे बेहतर निर्णायक होते हैं। इसलिए, नागरिकों के फीडबैक का उपयोग केवल किसी सर्वेक्षण या रैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय, इस फीडबैक का उपयोग नगरपालिका सेवाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावी, किफायती और सुरक्षित तकनीकें विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि कई आईआईटी और अन्य वैज्ञानिक शोध संगठनों के साथ विभिन्न संस्थान इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक स्टार्टअप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के उद्यम स्वच्छता से जुड़ी वास्तविक समस्याओं के समाधान में महत?वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों की क्षमताएं बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये ही वे शहर हैं जो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी आवश्यकताएं और चुनौतियां अलग-अलग हैं। इनका विकास एक ऐसे राष्ट्रीय ढांचे के भीतर होना चाहिए, जो इनकी विशिष्ट समस्याओं और चुनौतियों का समाधान कर सके।

उन्होंने कहा कि टियर-2 शहरों के नियोजक, टियर-1 शहरों की वर्तमान समस्याओं से सीख सकते हैं और ऐसा करने के लिए, उन्हें टियर-1 शहरों के नियोजकों के अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार', भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित करते हैं और 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं।

सशक्त और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रभावी संस्थाओं और लोक सेवकों की आवश्यकता है: ओम बिरला



नई दिल्ली,एजेंसी। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज इस बात पर जोर दिया कि एक सशक्त और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रभावी संस्थाओं और नागरिकों की आकांक्षाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील लोक सेवकों की आवश्यकता है। उन्होंने रेखांकित किया कि पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, नियमित रूप से लोगों के साथ संवाद करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों की गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जन विश्वास प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है। उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता, सुलभता और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से नागरिकों का विश्वास अर्जित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद संस्था के रूप में देखा जाना चाहिए जो लोगों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करती है। बिरला ने ये टिप्पणियां संसद भवन परिसर में आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह के साथ बातचीत के दौरान कीं। उन्होंने उनका आह्वान किया कि वे स्वयं को पूरी निष्ठा के साथ लोगों और राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें।

श्री बिरला ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे जन कल्याण को अपने पेशेवर आचरण के केंद्र में रखते हुए प्रतिबद्धता, निष्ठा, संवेदनशीलता और जवाबदेही की गहरी भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, लोक सभा अध्यक्ष ने युवा अधिकारियों को अपराध की रोकथाम और पहचान के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल उपकरणों, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक जांच तकनीकों का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग परिचालन दक्षता को बढ़ा सकती है, प्रतिक्रियाशीलता में सुधार कर सकती है और समग्र कानून-व्यवस्था ढांचे को मजबूत कर सकती है। बिरला ने आगे कहा कि समाज के सामने चुनौतियां लगातार बदल रही हैं और परिवीक्षाधीन अधिकारियों का आह्वान किया कि वे नए विचारों के लिए खुले रहें, अपनी पेशेवर क्षमताओं को निरंतर उन्नत करें और पुलिसिंग के लिए नवीन दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी पुलिसिंग में तकनीकी प्रगति के साथ मानवीय संवेदनशीलता और करुणा का समन्वय होना चाहिए।

सड़क उपयोगकर्ताओं से दुर्व्यवहार पर बिजवासन टोल एजेंसी पर कार्रवाई, एक महीने के लिए प्रतिबंधित

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले में बिजवासन टोल प्लाजा की शुल्क वसूली एजेंसी मेसर्स रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे एक महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। प्राधिकरण ने एजेंसी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई पांच नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग-248बीबी पर स्थित बिजवासन शुल्क प्लाजा पर एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा सड़क उपयोगकर्ताओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण की गई है। एनएचएआई ने इस मामले में एजेंसी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें एजेंसी और उसके मालिकों एवं निदेशकों को एक साल के लिए प्राधिकरण के भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया है। प्राधिकरण ने एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह 14 नवंबर को शुल्क प्लाजा का कार्यभार नई एजेंसी को सौंप दे। एनएचएआई के अनुसार, अनुबंध की शर्तों के तहत शुल्क वसूली एजेंसी की जिम्मेदारी है कि टोल प्लाजा पर तैनात उसके कर्मचारी उचित आचरण, अनुशासन और व्यवहार बनाए रखें।

पांच नवंबर की घटना से स्पष्ट हुआ कि एजेंसी अपने कर्मचारियों की निगरानी करने और अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने में विफल रही। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा है कि टोल प्लाजा पर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अंतरिक्ष, एयरोस्पेस और अनुसंधान सहयोग पर इटली के मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह बुधवार को तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर इटली के लिए रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोप के साथ भारत के वैज्ञानिक जुड़ाव को मजबूत करना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को आगे बढ़ाना है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री इटली के अंतरिक्ष, एयरोस्पेस और अनुसंधान सहयोग से जुड़े मंत्रियों सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अहम वार्ता करेंगे। इस यात्रा के दौरान उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें, रोम में दूसरा भारत-इटली विज्ञान एवं नवाचार संवाद 2026 तथा ट्रिएस्टे के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ संवाद आयोजित किए जाएंगे।

अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी, नई दरें आज से लागू



नई दिल्ली,एजेंसी। त्योहारी सीजन में प्रमुख डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमतों में इजाफा किया है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू होंगी। इन कंपनियों ने दूध की खरीद कीमतों में वृद्धि और ईंधन खर्च बढ़ने सहित उत्पादन लागत में इजाफे को इस वृद्धि का कारण बताया है। दूध की कीमतों में इस बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर पड़ने के साथ खाद्य महंगाई भी बढ़ सकती है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) और मदर डेयरी ने इससे पहले इस साल मई में दूध की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की थी। वहीं, पिछले महीने कर्नाटक के लोकप्रिय डेयरी ब्रांड नंदिनी ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए थे।

अमूल ब्रांड के तहत दूध बेचने वाले जीसीएमएमएफ ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने 12 नवंबर, 2026 से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। इस तरह सहकारी संस्था ने देशभर में दूध के दाम में चार से पांच प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। जीसीएमएमएफ ने कहा, ''हमारे सबसे अधिक बिकने वाले अमूल ताजा टोंड दूध (तीन प्रतिशत वसा) की कीमत में केवल दो रुपये प्रति लीटर (3.3 फीसदी) की वृद्धि की गई है, जबकि 6 प्रतिशत वसा वाले अमूल गोल्ड दूध की कीमत 4 रुपये प्रति लीटर (5.5 फीसदी) बढ़ाई गई है। इसी तरह दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने अपने दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है। नई दरें 12 नवंबर से लागू होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मदर डेयरी के टोंड दूध (बड़ी मात्रा में बिक्री वाले) की कीमत 58 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, फुल क्रीम दूध (पाउच) की कीमत अब 72 रुपये के बजाय 76 रुपये प्रति लीटर होगी। पाउच वाले टोंड दूध की कीमत 60 रुपये से बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डबल टोंड दूध अब 54 रुपये के बजाय 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा गाय के दूध की कीमत भी 62 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मदर डेयरी के लिए भी किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ गई है। इसके चलते कंपनी ने उत्पादन लागत में हुई वृद्धि का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है। मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में अपने बिक्री केंद्रों, सामान्य खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 35 लाख लीटर दूध बेचती है। देशभर में कंपनी की कुल दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से अधिक है।

भारत विकास की नई ऊंचाइयों पर, विपक्ष की राजनीति गिर रही नए निम्न स्तर पर: भाजपा



नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति लगातार नए निम्न स्तर पर जाती दिखाई दे रही है।

बुधवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'शो कॉल्ड डेड इकोनॉमी' (कथित मृत अर्थव्यवस्था) कहा था, लेकिन इसी अर्थव्यवस्था ने धनतेरस के दिन सोने-चांदी की खरीदारी के मामले में अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने दावा किया कि धनतेरस पर भारत में एक दिन में जितनी सोने-चांदी की खरीदारी हुई, उतनी खरीदारी पूरा यूरोप तीन महीने में करता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि विपक्ष के नेताओं के मन में भारत की परंपराओं, धर्म और संस्कृति के प्रति कितनी अवमानना और नकारात्मकता भरी हुई है। भारत लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन विपक्ष देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय निराधार टिप्पणियां करने में लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि खरगे जिस कर्नाटक राज्य से आते हैं, वहां कन्नड़ भाषा में त्योहार के लिए 'उत्सव' या 'हब्बा' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में 'ईद' शब्द कहां से आ गया?

प्रधानमंत्री 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे



नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13-14 नवंबर को कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे। वे 13 नवंबर को बेंगलुरु में सुबह लगभग 10:45 बजे प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:45 बजे प्रधानमंत्री तवरेकेरे से आईआईएम बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और उसमें सफर करेंगे। दोपहर लगभग 1:15 बजे प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद प्रधानमंत्री मैसूरु जाएंगे जहां दोपहर लगभग 3:30 बजे वे भारत वन में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम लगभग 4 बजे, प्रधानमंत्री कॉसमॉस-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करेंगे। वे इस अवसर पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 14 नवंबर को, प्रधानमंत्री गुजरात के बनासकांठा स्थित अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। अंबाजी मंदिर 51 पूजनीय शक्तिपीठों में एक है।

प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (एस-व्यास) के आवासीय मुख्यालय परिसर, प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर स्वर्ण जयंती प्रशासनिक खंड का शिलान्यास करेंगे और तिरुवनंतपुरम, केरल में एस-व्यासा ऑफ-कैंपस (मुख्य परिसर से बाहर स्थित केंद्र) का शुभारंभ करेंगे। 13 से 23 नवंबर 2026 तक विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर आयोजित होने वाला यह स्वर्ण जयंती समारोह संस्था-निर्माण और सेवा के पांच दशकों का प्रतीक है। 1975 में स्थापित, प्रशांति कुटीरम की स्थापना आधुनिक विज्ञान को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एस-व्यासा का केंद्र है, जिसे 2002 में मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था और यह योग में शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में 1926 में बेंगलुरु में जन्मे प्रख्यात विचारक, लेखक और संगठनकर्ता श्री होंगसांद्रा वेंकटरमैया शेषाद्रि जी की जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी। वे 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 1987 से 2000 तक इसके सरकार्यवाह रहे। वे एस-व्यास के दूरदर्शियों में से एक थे और उनकी प्रेरणा तथा मार्गदर्शन ने दशकों से प्रशांति कुटीरम के विकास को आकार देने और संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन आवागमन, विद्युत पारेषण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और रेलवे सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हैं।

सोनिया गांधी की किताब गांधी परिवार की दागदार छवि चमकाने की कोशिश, सिखों को देती है दर्द : सिरसा

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को कटघरे में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि यह किताब संस्मरण नहीं, गांधी परिवार की दागदार छवि चमकाने की कोशिश की है। यह किताब गांधी परिवार को बचाती है, आयोग में नामित कांग्रेस नेताओं को बचाती है और सिख कौम को सिर्फ दर्द देती है। मंत्री सिरसा ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने आंसुओं का ज़िक्र किया। इंदिरा गांधी के आंसुओं का जिक्र किया। राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन जिन सिख परिवारों के घर जले, जिनके बच्चे अनाथ हुए और जिनकी महिलाओं ने अपने पति और बेटे खोए, उनके लिए जवाबदेही की एक लाइन नहीं। 42 साल से ये परिवार सच का इंतजार कर रहे हैं। इस किताब ने उन्हें सिर्फ दर्द का अहसास दिया है।



मंत्री सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि किताब खुद अपना जुर्म कबूल करती है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि 'अकेले राजधानी में दो हजार से ज्यादा लोग सबसे क्रूर और बेरहम तरीके से मारे गए। उसी चैप्टर में वह लिखती हैं कि उनके आंसू सूख गए थे। मंत्री सिरसा ने कहा कि जब सिखों का कत्ल हो रहा था, तब उनके आंसू सूख गए। वह खुद मानती हैं कि 2,000 से ज़्यादा सिख बेरहमी से मारे गए। तो कातिलों के नाम कहां हैं ? गिनती उन्हें पता है, नाम वह छिपा रही हैं। वह लिखती हैं कि राजीव गांधी 'किसी भी तरह उन जघन्य कृत्यों को अधिकृत नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि एक लाइन में राजीव गांधी को निर्दोष किया गया। यह संस्मरण नहीं, किताब की शक्ल में क्लीन चिट है। मंत्री सिरसा ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ता सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे। फिर भी 544 पन्नों में इनका नाम एक बार भी नहीं। आखिर किसे बचाया जा रहा है ? वह 1984 को 'देश के इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय' कहती हैं। 'शर्मनाक शब्द मिल गया, माफी शब्द नहीं मिला। पूरे अध्याय में उनकी तरफ से माफी का एक शब्द नहीं। 'सोनिया गांधी अपनी 544 पन्नों की किताब बिलॉन्गिंग: प्रेम की यात्रा में 1984 को एक 'शर्मनाक अध्याय' कहती हैं। लेकिन शर्मनाक कह देना माफी नहीं होती। वह लिखती हैं कि त्रासदी के बाद पंजाब के सिखों ने कांग्रेस को कई बार सत्ता में लौटाया। सिखों के वोट को उन्होंने अपनी बेगुनाही का प्रमाणपत्र बना लिया। वोट माफी नहीं होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर वह लिखती हैं कि सिख कौम के लिए यह 'बेअदबी से कम नहीं था।' पछतावा बैठक खाने में रहा और टैंक दरबार साहिब में गए। बाबरी विध्वंस के लिए वह 'दुखद' शब्द इस्तेमाल करती हैं। एक ढांचे के लिए दुखद और सिखों के नरसंहार पर आंसुओं से खाली। यही इस किताब का सच है। मंत्री सिरसा ने कहा कि सोनिया गांधी खुद आयोगों का जिक्र करती हैं, तो उनके निष्कर्षों से भाग नहीं सकतीं। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर मारवाह जांच को पूरा होने से पहले रोक दिया गया। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग के बाद अलग समितियां बनीं। आहूजा समिति ने दिल्ली में 2,733 मौतें दर्ज कीं, जबकि पूरे देश में यह संख्या 3,325 थी। कपूर-मित्तल समिति ने 72 पुलिस अधिकारियों की पहचान की। जैन-बनर्जी समिति ने सज्जन कुमार और ब्रह्मानंद गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की। जैन-अग्रवाल समिति ने 669 पुराने शपथपत्रों, 415 नए शपथपत्रों और 403 प्राथमिकी की जांच की। उसने पुलिस जांच को सतही और गलत बताया। उसने एचकेएल. भगत, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री और जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की।

पराली प्रदूषण के नाम पर किसान को प्रताड़ित करना बंद करें सरकारें : भारतीय किसान संघ

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ) द्वारा पराली और किसानों को लेकर दी गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों और सुझावों का देश के सबसे बड़े किसान संगठन, भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि देश का शीर्ष न्यायालय प्रदूषण को लेकर अत्यंत गंभीर और चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने पर उठाई गई कड़ी आपत्ति से यह स्पष्ट हो गया है कि किसान प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को कागजी कार्यवाही छोड़कर जमीनी स्तर पर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान कर समाधान तलाशने चाहिए, न कि हर बार किसान को बलि का बकरा बनाना चाहिए।



मोहिनी मोहन मिश्र ने कोर्ट के सुझावों का जिक्र करते हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 का उदाहरण देते हुए बताया है कि लॉकडाउन के दौरान भी पराली जल रही थी, फिर भी दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ था, जो यह दर्शाता है कि प्रदूषण के पीछे अन्य बड़े कारक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान संघ सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव का समर्थन करता है जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सरकार फसलों की खरीद करती है, उसी तर्ज पर पराली की भी सरकारी खरीद या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिले और वे पराली जलाने के बजाय उसे बेच सकें। महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि उद्योग व गाड़ियां ही प्रदूषण की मुख्य जनक हैं। इसके लिए किसानों को निशाना बनाना अनुचित है। राज्य सरकारों व प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर अमल करते हुए उत्सर्जन तथा वाहनों के धुएं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय किसान संघ ने पुरजोर मांग उठाई है कि सरकारें पराली के नाम पर किसानों पर लगाए गए सभी जुर्माने और दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त करे।

भाई दूज के दिन फीकी पड़ी सोने की चमक, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज भाई दूज के दिन सोने के भाव में कमजोरी नजर आ रही है। चेन्नई के अलावा देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना आज 1,770 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। वहीं चेन्नई में सोने के भाव में 450 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 490 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह चमकीली धातु आज भी सोमवार के भाव पर ही कारोबार कर रही है।

कीमत में बदलाव होने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,44,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,30,790 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,32,110 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण यह चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज भी 2,04,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,42,830 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,42,680 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,30,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

छठ पूजा करने की सुविधा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि छठ पूजा गहरी आस्था और श्रद्धा का पर्व है। प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। पर्व शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जानी चाहिए, ताकि सार्वजनिक सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। यह बात विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को रोहिणी के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि चार दिवसीय छठ पूजा का आयोजन 13 से 16 नवंबर तक किया जाएगा।



निरीक्षण के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने सेक्टर-7 स्थित रामलीला मैदान, राजा विहार, सूरज पार्क, सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के निकट तथा सेक्टर-15 के बी-ब्लॉक सहित पांच स्थानों का दौरा किया। उन्होंने छठ पूजा के मद्देनजर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, आवागमन की सुविधा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह तैयार और क्रियाशील होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता ने विभिन्न स्थानों पर तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित नागरिक एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पांचों स्थानों पर निर्धारित समय से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दिल्ली में हजारों परिवारों के लिए छठ पूजा के विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का उल्लेख करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रशासन को श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहना चाहिए। उन्होंने महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया, ताकि 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होने वाला यह चार दिवसीय पर्व शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक ढंग से संपन्न हो सके।

छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बढ़ाई विशेष ट्रेनों की संख्या



नई दिल्ली, एजेंसी। छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन बढ़ाया गया है। बुधवार को दिल्ली क्षेत्र से कुल 31 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जबकि गुरुवार को 29 विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ और मांग के अनुसार अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे के अनुसार, बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10, आनंद विहार टर्मिनल से आठ, शकूरबस्ती से सात, हजरत निजामुद्दीन से चार, दिल्ली जंक्शन से एक और रोहतक से एक विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। इसी तरह, 12 नवंबर को दिल्ली क्षेत्र से चलने वाली 29 विशेष रेलगाड़ियों में नई दिल्ली से सात, आनंद विहार टर्मिनल से सात, शकूरबस्ती से पांच, हजरत निजामुद्दीन से पांच, दिल्ली जंक्शन से तीन, रोहतक से एक और दिल्ली सराय रोहिल्ला से एक रेलगाड़ी शामिल है। रेलवे ने बताया कि मंगलवार, 10 नवंबर को भी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ की निगरानी के बाद पहले से निर्धारित 27 विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त अल्प सूचना पर तीन अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं। उत्तर रेलवे के अधिकारी बुधवार को भी दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही और भीड़ की लगातार निगरानी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित रेलवे मुख्यालय और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशनों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं और भीड़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

छठ पूजा की तैयारियों का मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हाथी घाट पर लिया जायजा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को आईटीओ स्थित हाथी घाट का दौरा कर वहां छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने घाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे।

दिल्ली में लाखों श्रद्धालुओं के छठ पूजा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए सरकार द्वारा राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छठ पूजा के लिए दिल्ली में कुल 996 स्थानों पर 1,482 घाटों की व्यवस्था की गई है। इनमें 53 स्थानों पर 81 स्थायी घाट, 914 स्थानों पर 1,372 अस्थायी घाट और यमुना नदी के किनारे 29 स्थानों पर 29 घाट शामिल हैं। तैयारियों को समय पर पूरा करने और व्यवस्थाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 74 एजेंसियों को लगाया गया है और 155 कार्य आवंटित किए गए हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा घाटों पर आवश्यक सुविधाएं



उपलब्ध कराने, साफ-सफाई और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। तैयारियों के तहत घाटों की साफ-सफाई, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, श्रद्धालुओं के आने-जाने की सुविधा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, वहां व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दोनों विभागों के बीच समन्वय के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूजा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो जाएं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में रहने वाले लाखों परिवारों, विशेषकर हमारे पूर्वांचली भाई-बहनों के लिए बहुत भावनात्मक और आस्था से जुड़ा पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का यह अवसर हर परिवार के लिए बहुत खास होता है।

दिल्ली एनएसयूआई नेता छात्राओं को एनआरआई पुरुषों के पास भेजने के आरोपों में घिरा, अभाविप की एनआईए से जांच कराने की मांग

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज के एनएसयूआई उपाध्यक्ष अनस खान पर छात्राओं को पैसे और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर एनआरआई पुरुषों के साथ भेजने से संबंधित कथित संदेश सामने आने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है। अभाविप का आरोप है कि एनआरआई प्रायोजित कार्यक्रम के नाम पर छात्राओं से संपर्क स्थापित किया जा रहा था और उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर चयन की बातें भी संदेशों में सामने आई हैं। इस मामले में कॉलेज प्रशासन अनस खान को निलंबित कर चुका है।

अभाविप ने कहा कि छात्राओं को आर्थिक प्रलोभन देकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल करने का मामला संभावित मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे संगठित अपराधों से जुड़े नेटवर्क की आशंका पैदा करता है। संगठन ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की व्यापक जांच कराई जाए, ताकि एनआरआई संपर्कों, आर्थिक लेन-देन और संभावित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका का पता लगाया जा सके। अभाविप ने यह भी दावा किया कि पिछले माह एनएसयूआई से जुड़े व्यक्तियों द्वारा एक कार्यक्रम के लिए लड़कों को ले जाने से संबंधित इसी तरह की चैट सामने आई थी। संगठन ने लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एनएसयूआई के कार्यक्रमों के पीछे आर्थिक प्रलोभन और संदिग्ध नेटवर्क काम कर रहे हैं। अभाविप ने वर्ष 2018 में एनएसयूआई के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर संगठन की एक महिला पदाधिकारी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का भी उल्लेख किया। अभाविप ने इन घटनाओं को कांग्रेस और उसके छात्र संगठन के महिला सुरक्षा संबंधी दावों से जोड़कर सवाल उठाए।

मुनक नहर पर 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट का 12 को उद्घाटन करेंगे नितिन नबीन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार (12 नवंबर) को मुनक नहर के किनारे 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट उद्घाटन करेंगे। इस घाट का निर्माण दिल्ली सरकार ने कराया है। यह न केवल राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट होगा, बल्कि देश में किसी नहर के किनारे विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला और अनूठा आयोजन स्थल भी होगा। सिंगलपुर गांव के निकट लेबर चौक, मुनक नहर, शालीमार बाग में दोपहर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री व अन्य उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि मुनक नहर का यह कायाकल्प केवल निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि वर्षों से उपेक्षित पड़े क्षेत्र को आस्था, स्वच्छता, हरियाली और जनसुविधाओं के बड़े केंद्र में बदलने का प्रयास है। कभी गंदगी, मलबे और झाड़ियों से घिरी रहने वाली नहर को नया जीवन देने के लिए सरकार ने व्यापक सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनुपयोगी पड़े नहर के इस हिस्से से करीब 1,400 ट्रक मलबा, कचरा और अन्य गंदगी निकाली गई। इसके दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाकर एक सुंदर और व्यवस्थित छठ घाट विकसित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस परियोजना की लगातार निगरानी की और कई बार मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस भव्य घाट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लंबाई और सुव्यवस्थित निर्माण है। नहर के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां और सीमेंट की सड़कें बनाई जा रही हैं ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को सूर्योपासना के लिए घाट तक पहुंचने तथा पूजा-अर्चना करने में किसी तरह की परेशानी न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, टेंट व्यवस्था और पर्याप्त प्रकाश का प्रबंध किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के बैठने के लिए बेंच, हरियाली और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था भी परियोजना का हिस्सा है। नहर में स्वच्छ पानी के प्रवाह की व्यवस्था की जाएगी तथा विभिन्न स्थानों पर फव्वारे भी लगाए जाएंगे। इससे पूरे क्षेत्र को एक नया और आकर्षक स्वरूप मिलेगा। नहर के बीच तीन पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे आवागमन और दोनों किनारों के बीच संपर्क को बेहतर बनाया जा सके। परियोजना का अधिकतर काम पूरा हो चुका है। इस वर्ष छठ महापर्व पर पूरे 11 किलोमीटर क्षेत्र में पूजा-अर्चना की व्यवस्था की जा रही है, जबकि शेष विकास कार्य, पुलों का निर्माण और हरियाली से जुड़े कार्य आगामी दो-तीन महीनों में पूरे करने का लक्ष्य है।

दिल्ली नगर निगम ने छठ घाटों की तैयारियों का किया व्यापक निरीक्षण

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर तैयारियों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को घाटों पर साफ-सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, धूल नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक एवं डीडीसी चेयरमैन प्रद्युम्न राजपूत ने क्षेत्रीय पार्षदों तथा दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के उपायुक्त शशि प्रताप सिंह के साथ सागरपुर और महावीर एन्क्लेव स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र की वार्ड समिति के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय ने पश्चिमी क्षेत्र के उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री के साथ विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने विकासपुरी के न्यू कृष्णा पार्क स्थित छठ घाट पर जल एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की



सुविधाओं का जायजा लिया।

पूर्वी क्षेत्र के उपायुक्त अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी ने विभागाध्यक्षों के साथ आईटीओ के पास स्थित हाथी घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी किनारे कुछ स्थानों पर कचरा जमा होने और यमुना में तैरता हुआ कचरा दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यांत्रिक नौकाओं के माध्यम से नदी में तैरते कचरे को हटाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्माण एवं विध्वंस (सीएएंडडी) कचरे का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। घाटों पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव करने की योजना भी बनाई गई है।

निगम अधिकारियों को छठ पूजा से पहले, पूजा के दौरान और पूजा के बाद तक के लिए विस्तृत स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके तहत घाटों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाने, पूजा सामग्री के पृथक संग्रहण एवं उचित निस्तारण तथा प्रमुख स्थानों पर स्वच्छता संबंधी जागरूकता संदेशों वाले सूचना बोर्ड लगाने को कहा गया। निगम ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

एक नजर

धूल नियंत्रण नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले पांच निर्माण स्थल सील

गुरुग्राम,एजेंसी। वायु प्रदूषण की रोकथाम और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के निर्धारित उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम (उत्तर) की टीम ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पांच निर्माण स्थलों को सील कर दिया। इनमें से तीन निर्माण स्थल उद्योग विहार क्षेत्र में स्थित हैं। एचएसपीसीबी के एईई कामेश ने बुधवार को बताया कि निरीक्षण के दौरान इन निर्माण स्थलों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके अलावा संबंधित निर्माण स्थलों की ओर से एचएसपीसीबी के डस्ट पोर्टल से जुड़ी आवश्यक अनुपालन प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई थी। इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए पांचों स्थलों को सील करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल नियंत्रण के निर्धारित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र में निरीक्षण अभियान भी लगातार चलाया जाएगा, ताकि सीएक्यूएम के दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी के केमिकल टैंक में गिरने से तीन कर्मचारियों की मौत

गुरुग्राम। भौंडसी थाना क्षेत्र के जेल रोड स्थित संधार कंपनी में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। केमिकल टैंक में गिरने से तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर भौंडसी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी 21 वर्षीय आरीफ, नवादा निवासी 20 वर्षीय अनिल झा व बादशाहपुर की आरआर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय नरेश कुमार यहां जेल रोड स्थित संधार कंपनी में काम करते थे। बुधवार दोपहर तीनों कर्मचारी कंपनी परिसर में काम कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक अनियंत्रित होकर केमिकल टैंक में गिर गए। टैंक में मौजूद जहरीले रसायन और गैस की चपेट में आने से तीनों बेहोश हो गए। हादसे के बाद कंपनी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में तीनों को टैंक से बाहर निकालकर बादशाहपुर स्थित एकता अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए पार्क अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर भौंडसी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि कंपनी में केमिकल टैंक के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं और कर्मचारी किन परिस्थितियों में टैंक में गिरे। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

जांच में दोषी कर्मचारी पर मेहरबानी, डीसी के आदेश पर भी नहीं हटाया

गुरुग्राम। सदर बाजार से नगर निगम की टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा एक दुकानदार का अवैध रूप से सामान उठाने के मामले की जांच में दोषी ठहराया गया। नगराधीश (सीटीएम) के द्वारा जांच और उपायुक्त के आदेशों के बाद भी उस पर नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) ने कोई संज्ञान नहीं लिया। निगमायुक्त द्वारा उसे निष्कासित किया जाना था, मगर ऐसा करने की बजाय उसे शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। उसे तुरंत प्रभाव से ड्यूटी से निष्कासित नहीं करने पर पीड़ित ने सवाल उठाए हैं। नगर निगम गुरुग्राम की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के सदस्य मोहित शर्मा द्वारा सदर बाजार स्थित जैन जलेबी दुकान के सामने स्थित जैनेंद्र जैन नामक व्यक्ति की दुकान से अवैध कब्जा बताकर सामान उठाया गया था।

पीड़ित दुकानदार जैनेंद्र जैन ने बुधवार को बताया कि उन्होंने मोहित शर्मा द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर जिला उपायुक्त के समक्ष शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जिला उपायुक्त के निर्देशों पर नगराधीश (सीटीएम) ने इस मामले की गहनता से जांच की। 25 अप्रैल 2024 को नगराधीश द्वारा सौंपी गई जांच में कहा गया कि मोहित शर्मा द्वारा दुकानदार जैनेंद्र जैन का सामान उठाया जाना सही नहीं बल्कि अवैध कार्य था। साथ ही जांच में यह भी लिखा गया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा मोहित शर्मा को ऐसी चेकिंग के लिए मनोनीत किया गया है। यह भी समझ से परे है कि वह किस हैसियत से पुलिस बल का इंतजाम करता है। नगराधीश की जांच रिपोर्ट को लेकर जिला उपायुक्त की ओर से भी सात मई 2024 को निगमायुक्त को पत्र लिखकर मोहित शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। हैरानी की बात है कि तब से लेकर पांच अक्टूबर 2026 तक ढाई साल में निगमायुक्त गुरुग्राम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। छह अक्टूबर 2026 को मोहित शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने की बात कही गई।

गुरुग्रामः रेलवे रोड पर लापरवाही व कथित भ्रष्टाचार पर भी एक्शन लो सीएम साहबः पंकज डावर

गुरुग्राम,एजेंसी। कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने बुधवार को ओल्ड रेलवे रोड के डिवाइडर की दुर्दशा दिखाते हुए भाजपा सरकार, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार देखना है तो ओल्ड रेलवे रोड पर जाकर देख लीजिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रेलवे रोड पर हुए इस घटिया काम की जांच कराकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की जाए।



हकीकत तो यह है कि यह काम हुआ ही नहीं। पंकज डावर ने बुधवार को बताया कि कबीर भवन चौक से आगे रेलवे रोड तक डिवाइडर पर पांच महीने पहले लॉकिंग टाइलें लगाई गई थीं। काम इतना घटिया था कि कोई भी देखकर बता दे कि इसमें बड़ी लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार न हुआ होता तो यह काम बहुत बढ़िया हो जाता। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत इसमें दिख रही है। पहली बार जब यह डिवाइडर पर टाइलें लगाई गई तो ना टाइलों के लॉक मिलाए गए, ना लेवल सही किया गया। टाइलें बेतरतीब तरीके से, काफी गैप छोडक़र, ऊबड़-खाबड़ लगा दी गईं। डावर ने कहा कि उन्होंने नौ जुलाई 2026 को इस मुद्दे को उन्होंने उठाया था। आवाज उठाने के अगले ही दिन ठेकेदार ने टाइलों को दोबारा लगाने के नाम पर उखाडक़र एक जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन आज पांच महीने बीतने के बाद भी टाइलें ज्यों की त्यों पड़ी हैं। उन्हें दोबारा लगाने की शुरुआत तो क्या सोचा तक नहीं हुई है।

डावर ने कहा कि जनता की कमाई को इस तरह बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर सीएम साहब सच में भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना चाहते हैं तो रेलवे रोड पर इस लापरवाही पर भी एक्शन लें। इस काम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि इस काम के बिल पास हुए या नहीं, पेमेंट हुई या नहीं। दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।

गाजियाबाद में 5 मस्जिदें तोड़ने और नमाजियों पर फायरिंग का दावा निकला फर्जी

गाजियाबाद,एजेंसी। इंटरनेट मीडिया पर गाजियाबाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव से जुड़ी भ्रामक पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। एक्स पर दो अलग-अलग अकाउंट से गाजियाबाद में पांच मस्जिदों को तोड़ने और नमाज पढ़ रहे लोगों पर पुलिस की ओर से गोली चलाने का फर्जी दावा किया गया। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि घटना के विरोध में हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

साइबर क्राइम थाने में दोनों एक्स अकाउंट संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साइबर क्राइम थाने में तैनात उपनिरीक्षक सुशील कुमार की ओर से 10 नवंबर ने बताया कि वह मंगलवार को साइबर क्राइम थाने में मौजूद थे। इसी दौरान इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उनकी नजर दो पोस्ट पर पड़ी। इनमें गाजियाबाद में मस्जिदों को तोड़े जाने और पुलिस की ओर से नमाजियों पर गोली चलाने की बात कही गई थी। पोस्ट में जिस तरह से घटना का उल्लेख किया गया, उससे गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने का दावा भी किया गया था। पहली पोस्ट एक्स अकाउंट से दोपहर 12:07 बजे की गई थी।

इसमें अंग्रेजी में लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिन पहले पांच मस्जिदों को तोड़ दिया गया। उस दौरान मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे और गाजियाबाद पुलिस ने उन पर गोली चला दी। पोस्ट में आगे दावा किया गया कि घटना के विरोध में हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए हैं। इस तरह पोस्ट में मस्जिदों को तोड़े जाने, नमाजियों पर फायरिंग और उसके बाद बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने की बात कही गई थी। इसके करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12:36 बजे दूसरे अकाउंट से भी इसी तरह की पोस्ट की गई।

फरीदाबाद : परमजीत हत्याकांड के आरोपी ने चौकी में पिटाई के बाद मोनू ने हत्या की ठानी

फरीदाबाद। धनतेरस के दिन फरीदाबाद में हुए टेक महिंद्रा कंपनी के पूर्व एशिया हेड परमजीत धनखड़ (45) हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। घटना से पहले परमजीत के बेटे शौर्य और आरोपी मोनू शर्मा के बीच विवाद हुआ था। इसी की शिकायत देने परमजीत अपने दोस्तों के साथ अनखीर चौकी गया था। वहां मोनू भी पहुंच गया। परमजीत के दोस्तों ने उसे देखते ही पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने तब तो मामला सुलझा दिया। मोनू चौकी से मेडिकल कराने की बात कहकर निकल गया।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि इसी घटना के बाद उसने परमजीत की हत्या करने की ठान ली थी। धनतेरस की शाम उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 9 गोलियां मारकर परमजीत की हत्या कर दी। पुलिस को उसके पास से 67 गोलियां मिली हैं। वारदात के बाद मोनू कार लेकर फरार हो गया। यहां से सीधे पंजाब के पटियाला में अपनी ससुराल पहुंचा। वहां कार और खून से सनी टीशर्ट छिपाई। पुलिस अब दोनों चीजों की बरामदगी के लिए उसे पंजाब लेकर जाएगी। हिसार निवासी परमजीत परिवार के साथ सेक्टर-21सी की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। मोनू तीसरे फ्लोर पर रहता था। वह स्क्रैप का कारोबार करता है। पुलिस के मुताबिक, दोनों परिवारों के बीच करीब चार साल से विवाद चल रहा था। मोनू जब जर्मन शेफर्ड कुत्ता लेकर आया था, तभी से कहासुनी शुरू हुई थी। आरोप है कि उसका नौकर कुत्ते को परमजीत के घर के सामने शौच कराता था। इस बात पर कई बार झगड़ा हुआ। बाद में गाड़ी खड़ी करने और पार्किंग की जगह को लेकर भी विवाद बढ़ता गया। परमजीत के बेटे शौर्य और मोनू के बीच धनतेरस की सुबह पार्किंग का गेट तोडऩे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि मोनू ने गाली-गलौज की थी। इसके बाद अनखीर चौकी में शिकायत दी गई। परमजीत जिम से सीधे चौकी पहुंचे थे। परमजीत के बेटे शौर्य की शिकायत पर पुलिस ने मोनू की पत्नी, बेटे और बेटी को भी हत्या के लिए उकसाने के आरोप में नामजद किया है। तीनों फिलहाल फरार हैं। पुलिस आरोपी के घर का ताला खुलवाकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेगी। इससे वारदात के समय परिवार के सदस्यों की मौजूदगी और उनकी भूमिका की जांच होगी। पुलिस जांच में मोनू के पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी।

स्कूटी टकराने के विवाद में युवक की हत्या करने वाला मुख्य आरोपित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। उत्तर प्रदेश के जनपद गोतमबुद्धनगर नोएडा में स्कूटी टकराने के विवाद में एक युवक की हत्या करने और दूसरे को अधमरा करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित को थाना फेस-1 पुलिस ने बुधवार सुबह को एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली इसके पैर में लगी है। इसके एक अन्य साथी को पुलिस ने बीती रात को गिरफ्तार किया था।



पुलिस उपायुक्त नोएडा प्रीति यादव ने बताया कि थाना फेस-1 पुलिस आज सुबह को नयाबांस गांव के पास स्थित पार्क के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि आठ नवंबर को एक युवक की सिर फोड़कर हत्या करने वाले आरोपित पार्क में बैठे हैं। वे कहीं भागने की फिराक में है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पार्क में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस को देख बदमाश वहां से भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें घेरा तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली आफताब उर्फ तुलसी पुत्र रियाजुद्दीन के पैर में लगी है। उन्होंने बताया कि इसके पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देशी तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आठ नवंबर की रात को स्कूटी टकराने के विवाद में आरोपित ने अपने साथियों के संग मिलकर अमित नामक युवक की हत्या कर दी थी। उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी। उसका एक साथी शिवम गंभीर रूप से घायल है। वह उपचाराधिन है। इस मामले में हत्या और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा थाना फेस वन में दर्ज है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ पूर्व में तीन मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात को थाना पुलिस ने इस घटना में शामिल एक किशोर को गिरफ्तार किया था।

नूंहः 41वें दिन मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज का आंदोलन पड़ा ठंडा, कैंपस से गायब हुई भीड़

नूंह,एजेंसी। नूंह के पल्ला गांव स्थित मेवात वक्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 40 दिनों से जारी आंदोलन के 41वें दिन बुधवार को माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जिस कॉलेज परिसर में पिछले कई दिनों से भारी भीड़, नारेबाजी और हंगामा दिखाई दे रहा था, वहां आज सन्नाटा पसरा रहा। आंदोलन के दौरान बाहर से आए लोगों की भीड़ भी अब कॉलेज परिसर में दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा पहचान कर बाहरी लोगों को कॉलेज कैंपस से बाहर किए जाने के बाद अब परिसर में मुख्य रूप से कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ही नजर आ रहे हैं।

धरना स्थल की तस्वीर भी बदली हुई दिखाई दी। जहां पहले बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठते थे, वहीं बुधवार को कुछ ही छात्र इधर-उधर बैठे नजर आए। इसके अलावा कॉलेज के कुछ लेक्चरर और कर्मचारी भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। पूरे कॉलेज परिसर में न तो पहले जैसी नारेबाजी सुनाई दी और न ही किसी तरह का हंगामा देखने को मिला। छात्र सामान्य रूप से कॉलेज परिसर में बैठे दिखाई दिए। आंदोलन के इस बदले माहौल की एक बड़ी वजह मंगलवार को हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासन की ओर से छात्रों की सभी मांगों को लिखित



रूप में मंजूरी दिया जाना माना जा रहा है। मांगों पर सहमति बनने के बाद कुछ छात्रों ने आंदोलन को लेकर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि उनकी मांगें मान ली गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि उन्हें इस आंदोलन में इस्तेमाल किया गया, जिसका उन्हें अफसोस है। वहीं कॉलेज के लेक्चरर का कहना है कि यह आंदोलन पिछले 40 दिनों से चल रहा है और बुधवार को 41वां दिन है। आंदोलन शुरू करने के पीछे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और कॉलेज के स्टाफ को समय पर वेतन दिलाने की मांग प्रमुख थी। इस संबंध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया था। ज्ञापन में मांग की गई थी कि यदि वक्फ बोर्ड कॉलेज का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो इसे हरियाणा सरकार के अधीन कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शिक्षकों व कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।

घर-प्लॉट खरीदना अब महंगा, नए सर्किल रेट पर इस महीने लग सकती है मुहर

गाजियाबाद। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा का त्योहार बीत चुका है। बुधवार को भाई दूज का त्योहार है। इसके बाद छुट्टियां खत्म हो जाएगी और सरकारी कार्यालयों में लंबित कार्यों की फाइलें आगे बढ़ाई जाएंगी। इसी क्रम में जिले में जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाया जाना है, उम्मीद है कि नवंबर अंत या दिसंबर तक सर्किल रेट की नई दर जिले में लागू हो जाएगी। हालांकि, निबंधन विभाग के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जिले में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए प्रक्रिया अक्टूबर माह में शुरू हो चुकी है।

इस संबंध में एक बार बैठक भी आयोजित हो चुकी है। त्योहारों के कारण अगले दौर की बैठक को को स्थगित कर दिया गया था। निबंधन विभाग की ओर से जिले में सर्वे कराया जा रहा है, जिससे कि यह पता चल सके कि किस क्षेत्र में जमीन अधिक खरीदी जा रही हैं। किस तरफ तेजी से बसावट हो रही है। सर्वे पूरा होने के बाद सर्किल रेट की प्रस्तावित दर तैयार कर फाइल जिलाधिकारी के समक्ष पेश की जाएगी।

गुरुग्राम आईटीआई में पीएम इंटर्नशिप योजना पर जागरुकता कार्यशाला

गुरुग्राम,एजेंसी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के प्रधानाचार्य रविन्द्र कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं को उद्योगों से जोडऩे और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है, ताकि वे नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। कार्यशाला में प्रधानाचार्य ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक रोजगार अधिकारी, आईटीआई के स्टाफ मेम्बर और उद्योग संगठन प्रतिनिधियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में छह से नौ माह की पेड इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रुपये होनी चाहिए। प्रधानाचार्य ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभों के बारे में भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है, जिससे युवा घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर जानकारी के अभाव में पात्र युवा भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए जागरुकता सबसे जरूरी है। कार्यशाला के साथ ही संस्थान परिसर में रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। मेले में एचबीएसएस ई-मोबिलिटी और बी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड ने पास आउट पासआउट छात्र-छात्राओं को जॉब और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान किए।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर नर्सिंग ऑफिसर्स में उठे विरोध के स्वर

गुरुग्राम। हरियाणा में नर्सिंग ऑफिसर्स ने ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य प्रधान विनीता बांगड़ ने बुधवार को कहा कि सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ धोखा किया है। बिना सूचित किए ट्रांसफर का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। अब सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।

विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने पांच-छह अक्टूबर 2026 को हड़ताल की थी। उस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डा. सुमिता मिश्रा ने इस आश्वासन पर हड़ताल समाप्त कराई थी कि वे मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर यह पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करेंगी। इसके बाद इस पर क्या निर्णय हुआ, क्या चर्चा हुई, इसकी कोई जानकारी नर्सिंग एसोसिएशन को नहीं दी गई। अब अचानक बिना सूचित किए ट्रांसफर के आदेश निकाल दिए गए हैं। यह नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ सरासर धोखा है। अब अनिश्चिकालीन हड़ताल होगी। क्योंकि जबरन ट्रांसफर पॉलिसी थोपकर सरकार नर्सिंग ऑफिसर्स को अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। जल्द ही हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। हड़ताल में जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने सभी नर्सिंग ऑफिसर्स से एकजुट होकर आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। विनीता बांगड़ ने बताया कि हरियाणा के सभी जिलों के नर्सिंग एसोसिएशन प्रधान अपने-अपने जिलों में 14 नवंबर 2026 तक मीटिंग रखेंगे। सभी जिलों से सुझाव लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। विनीता बांगड़ ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, रात में परिवहन की सुविधा का ख्याल नहीं रख रही। नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी आम कर्मचारियों यानी अन्य विभागों के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है। हमारी कोई 9 से 5 बजे की ड्यूटी नहीं है। सुबह, दोपहर, रात का ड्यूटी शेड्यूल रहता है। हम 24 घंटे की सेवा देते हैं।

सीईआईआर पोर्टल से बरामद किए 42 लाख के मोबाइल

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद पुलिस की सेंट्रल जोन साइबर सेल ने तकनीकी दक्षता और डिजिटल ट्रैकिंग के प्रभावी उपयोग से आठ लाख रुपये से अधिक कीमत के 42 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डीसीपी सेंट्रल राजेश मोहन ने बुधवार को अपने कार्यालय में बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। इस कार्रवाई से नागरिकों को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिली है। पुलिस प्रवक्ता अनुसार गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए सेंट्रल जोन की साइबर सेल ने केंद्र सरकार के सीईआईआर (सेंट्रल इक्यूपमेंट एडेंटी रजिस्र्ट) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विश्लेषण किया।

तकनीकी जांच के दौरान मोबाइल फोन के ईएमईआई नंबर, नेटवर्क संबंधी जानकारी, डिजिटल ट्रैकिंग और उपलब्ध तकनीकी इनपुट का उपयोग कर मोबाइल फोन की पहचान की गई। जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फोन के उपयोग एवं उनकी उपलब्ध लोकेशन से संबंधित जानकारी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस टीम 42 मोबाइल फोन बरामद करने में सफल रही। बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये से



अधिक है। लंबे समय से अपने मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके नागरिकों को जब उनके फोन मिले तो उन्होंने खुशी जाहिर की। मोबाइल फोन मालिकों ने फरीदाबाद पुलिस की तकनीकी कार्यप्रणाली और तत्परता की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। डीसीपी सेंट्रल राजेश मोहन ने नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम होने पर तत्काल संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं और भारत सरकार के ष्टश्वड्ढक्र पोर्टल पर भी अनुरोध प्रस्तुत करें। समय पर शिकायत दर्ज होने से मोबाइल फोन को ब्लॉक कराने, उसकी पहचान एवं बरामदगी के प्रयासों में सहायता मिलती है और उसके संभावित दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है।

विकास की वेदी पर बलि चढ़ती प्रकृति

अशोक भाटिया



अरुणाचल प्रदेश केशी योमी और सियांग जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिक मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही इस परियोजना के लिए लगभग 470 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा, जिसके कारण इस अति-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र से एक लाख से अधिक हरे-भरे पेड़ों को काट दिया जाएगा। यह खबर औद्योगिक और ढांचागत विकास के मोर्चे पर जितनी सकारात्मक लगती है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उतनी ही भयावह है। पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, अपने सघन वर्षावनों और दुर्लभ जैव-विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में विकास के नाम पर एक लाख से अधिक जीवित वृक्षों की सामूहिक बलि देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह प्राकृतिक तबाही वाकई अपरिहार्य थी? क्या इस अभूतपूर्व नुकसान की भरपाई संभव है? और इस विनाश के बदले अरुणाचल प्रदेश तथा वहां के मूल निवासियों को वास्तव में क्या हासिल होने वाला है? गौरतलब है कि बिजली घर, सुरंगें और भारी मशीनरी स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़े भूभाग की जरूरत है। इस विवाद में सबसे बुनियादी सवाल यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को उजाड़े बिना बांध का निर्माण संभव नहीं था? जलविद्युत परियोजनाओं की तकनीकी रूपरेखा पूरी तरह से नदियों के प्रवाह और पानी के विशाल संचय पर टिकी होती है। नायिंग परियोजना के लिए विशालकाय बांधजिस क्षेत्र में यह बांध प्रस्तावित है, वह उच्च संरक्षण मूल्य वाले घने जंगलों के अंतर्गत आता है। इंजीनियरिंग और जलविज्ञान के नियमों के मुताबिक, जब बांध के जरिए नदी के पानी को रोका जाता है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस डूब क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों और वनस्पतियों को पहले ही काट देना तकनीकी और सुरक्षा कारणों से जरूरी माना जाता है। यदि इन पेड़ों को बिना काटे वैसे ही पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाए, तो पानी के भीतर वे सड़ने लगते हैं। इस सड़न से बड़े पैमाने पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीनहाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है, जो पानी की गुणवत्ता को नष्ट कर पूरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देती हैं। यही वजह है कि जलाशय की जलधारण क्षमता बनाए रखने के लिए इन एक लाख पेड़ों को हटाना सरकारी ब्लूप्रिंट में एक व्यावहारिक विवशता बन जाता है।

जब हम एक लाख पेड़ काटने की बात करते हैं, तो प्रशासनिक फाइलों पर यह केवल एक निर्जीव संख्या की तरह दिखता है, लेकिन प्रकृति के विज्ञान में यह सदियों की अनवरत तपस्या का अंत है। इंसानी हाथों द्वारा लगाए जाने वाले कृत्रिम बागानों और प्राकृतिक वनों के बीच एक ऐसा अंतर होता है जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता। एक सामान्य पौधा लगाने के बाद उसे एक परिपक्व वृक्ष बनने में भले ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता हो, लेकिन जब हम एक वास्तविक जंगल की बात करते हैं, तो वह केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जटिल और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अरुणाचल प्रदेश के ये जंगल अत्यधिक घने वन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें सदियों पुराने विशालकाय ओक, पाइन और देवदार के वृक्ष शामिल हैं। इस तरह के एक समृद्ध वर्षावन को पूरी तरह से अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटने के लिए कम से कम 80 से 150 वर्ष का लंबा वक्त लगता है। इन प्राकृतिक वनों में कई स्तरों पर वनस्पतियां, मिट्टी की सूक्ष्म जैविक संरचना, कवक और स्थानीय जीव-जंतुओं का एक पूरा संसार विकसित होता है। विडंबना यह है कि इंसानी प्रयासों द्वारा किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण में लगाए गए पौधों में से केवल 20 से 25 प्रतिशत ही जीवित रह पाते हैं। इसलिए, कोई भी कृत्रिम रोपण कभी भी उस प्राकृतिक जैव-विविधता का विकल्प नहीं बन सकता जो प्रकृति ने सदियों के क्रमिक विकास से तैयार की है।

भारतीय वन कानूनों के तहत, जब भी किसी विकास परियोजना के लिए वन भूमि का डायवर्जन किया जाता है, तो निर्माण एजेंसी से 'प्रतिपूरक वनीकरण' के तहत भारी आर्थिक हर्जाना वसूला जाता है। नायिंग परियोजना के लिए भी समिति ने सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की संख्या से दोगुनी संख्या में नए पेड़ लगाने और नष्ट हुए वन्यजीव आवासों के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना का खर्च उठाना होगा। परंतु, इस हर्जाने की नीति में एक बहुत बड़ी भौगोलिक विसंगति हमेशा से मौजूद रही है। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80 प्रतिशत भूभाग पहले से ही सघन वनों से ढका हुआ है, जिसके कारण राज्य के भीतर वनीकरण के लिए अतिरिक्त गैर-वन भूमि मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूर्व की कई परियोजनाओं के अनुभवों को देखें, तो अरुणाचल में काटे जाने वाले वनों का हर्जाना और नया वनीकरण मध्य प्रदेश या अन्य मैदानी राज्यों में सैकड़ों किलोमीटर दूर खाली पड़ी भूमि पर करने का प्रस्ताव दिया जाता रहा है। यह प्रक्रिया कानूनी कागजों पर भले ही हर्जाना मान ली जाए, लेकिन पारिस्थितिकी के तराजू पर यह पूरी तरह निरर्थक है। अरुणाचल के संवेदनशील पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में जो एक लाख पेड़ कटेंगे, उससे वहां की स्थानीय जलवायु, वर्षा का चक्र, भूस्खलन की आवृत्ति और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसकी भरपाई देश के किसी अन्य कोने में पेड़ लगाकर कभी नहीं की जा सकती। इस भारी प्राकृतिक कीमत को चुकाने के बाद यह जानना जरूरी है कि इस पूरे सौदे से अरुणाचल प्रदेश और उसके नागरिकों को अंततः क्या हासिल होने वाला है। सरकार के आर्थिक तथा रणनीतिक रोडमैप के अनुसार, यह परियोजना अरुणाचल को बिजली आधिक्य राज्य बनाने और उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। इसके क्रियान्वयन से अरुणाचल प्रदेश को उत्पादित होने वाली कुल बिजली का 12 प्रतिशत हिस्सा रॉयल्टी के रूप में पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिसे ग्रिड या अन्य राज्यों को बेचकर राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, निर्माण और संचालन के चरणों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुदूरवर्ती और दुर्गम जिलों में पक्की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और आधुनिक स्कूलों का विकास होगा, जो स्थानीय कनेक्टिविटी और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा है; चीन की सीमा के निकट होने के कारण इस नदी के निचले हिस्से पर भारत द्वारा इन बड़े बांधों का निर्माण करना बेहद जरूरी है, ताकि ऊपरी तटीय क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए जा रहे विशाल बांधों के जवाब में भारत अपने अंतरराष्ट्रीय जल अधिकारों को मजबूती से सुरक्षित कर सके। निष्कर्ष के तौर पर यह स्पष्ट है कि 'नायिंग जलविद्युत परियोजना' को मंजूरी मिलना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक नीतियों की एक बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन एक लाख पेड़ों की यह सामूहिक बलि इस जीत पर पर्यावरण की ओर से एक गहरा दाग भी है। जब हम एक लाख पेड़ काटते हैं, तो हम केवल लकड़ी का नुकसान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम हिमालय की संवेदनशील और दरकती पहाड़ियों की जड़ों को कमजोर कर रहे होते हैं, जिससे भविष्य में विनाशकारी भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़ और बड़े पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण के इस अंतहीन टकराव में अब हमें पुराने प्रशासनिक तौर-तरीकों से हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। यदि इन पेड़ों को काटना एक अपरिहार्य तकनीकी मजबूरी है, तो इसके हर्जाने के तहत होने वाले वनीकरण को महज कागजी खानापूर्ति या दूसरे राज्यों में पेड़ लगाने की औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय सरकार और निर्माण कंपनियों को अरुणाचल के ही स्थानीय, भूस्खलन-संवेदनशील इलाकों में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके युद्धस्तर पर सघन वनों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि विकास केवल तभी तक टिकाऊ और सार्थक है जब तक प्रकृति हमें खुलकर सांस लेने की अनुमति देती है।

इस स्थिति का प्रभाव स्थानीय बाजारों और खुदरा मूल्यों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फसल अभी पूरी तरह बाजार में उतरी भी नहीं है कि खुदरा बाजारों में चावल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में सोना मसूरी, पोनी और स्वर्णा जैसी लोकप्रिय किस्मों के दाम 10 से 25 प्रतिशत तक उछल चुके हैं। वहीं प्रीमियम चावल के दाम कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़े हैं। जानकारों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध जैसे हालातों के चलते जहां एक ओर कई देश अपने घरेलू खाद्य भंडारों को सुरक्षित करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने से कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि पूसा के वैज्ञानिकों और कुछ धान विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि देश के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और अगेती तथा पिछैती किस्मों का सही संतुलन अंततः इस नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित हो सकता है। घरेलू बाजार के साथ-साथ इस मौसमी बदलाव और उत्पादन की अनिश्चितता का असर कृषि निर्यात पर भी पड़ने की पूरी आशंका है। भारत वैश्विक बाजार में बासमती और गैर-बासमती चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश ने लगभग 20.19 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया था, जिसका कुल मूल्य लगभग 12.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। चालू वर्ष में भी निर्यात को लेकर शुरुआती अनुमान अच्छे थे।

धान के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकूल असर

पंकज चतुर्वेदी



देश की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर मौसम की अनिश्चितता और अल नीनो का गंभीर साया मंडराता नजर आ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार मानसून का कमजोर और असमान रहना खरीफ सीजन के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, जिसका असर देश की मुख्य खाद्यान्न फसल यानी धान के रकबे और उसकी कुल पैदावार पर पड़ने की आशंका है। हालांकि, भारत में कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 149.07 से 150.18 मिलियन टन धान का बंपर उत्पादन हुआ था। देश दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक होने के साथ-साथ वर्ष 2012 से सबसे बड़ा निर्यातक भी बना हुआ है, किंतु इस बार की मौसमी परिस्थितियां चिंता का विषय जरूर बन रही हैं। मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान कृषि प्रधान राज्यों में मानसून की बेरुखी और सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज किए जाने के कारण धान की रोपाई और कुल रकबे में भारी गिरावट आई है। आंकड़ों के अनुसार देश भर में धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले घटकर काफी नीचे आ गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई वाले क्षेत्रों तथा हरियाणा जैसे राज्यों में उत्पादन प्रभावित होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा, कटाई के समय बेमौसम बारिश के कारण मंडियों में पहुंचे धान का एक बड़ा हिस्सा भीग गया, जिससे उनमें नमी की मात्रा सामान्य से 20 से 22 प्रतिशत तक बढ़ गई है। नमी अधिक होने के कारण मिल मालिक और खरीदार भी धान की खरीद में गहरी रुचि नहीं दिखा रहे हैं और किसानों को कम दाम देने पर मजबूर कर रहे हैं।

इस स्थिति का प्रभाव स्थानीय बाजारों और खुदरा मूल्यों पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। फसल अभी पूरी तरह बाजार में उतरी भी नहीं है कि खुदरा बाजारों में चावल की कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में सोना मसूरी, पोनी और स्वर्णा जैसी लोकप्रिय किस्मों के दाम 10 से 25 प्रतिशत तक उछल चुके हैं। वहीं प्रीमियम चावल के दाम कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और भी अधिक बढ़े हैं। जानकारों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और युद्ध जैसे हालातों के चलते जहां एक ओर कई देश अपने घरेलू खाद्य भंडारों को सुरक्षित करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने से कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि पूसा के वैज्ञानिकों और कुछ धान विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि देश के पास पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है और अगेती तथा पिछैती किस्मों का सही संतुलन अंततः इस नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित हो सकता है। घरेलू बाजार के साथ-साथ इस मौसमी बदलाव और उत्पादन की अनिश्चितता का असर कृषि निर्यात पर भी पड़ने की पूरी आशंका है। भारत वैश्विक बाजार में बासमती और गैर-बासमती चावल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश ने लगभग 20.19 मिलियन मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया था, जिसका कुल मूल्य लगभग 12.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। चालू वर्ष में भी निर्यात को लेकर शुरुआती अनुमान अच्छे थे। सऊदी अरब, बेनिन, इराक, ईरान, गिनी, कोट डी आइवर, संयुक्त अरब अमीरात और टोगो जैसे देश हमारे चावल के प्रमुख खरीदार हैं। लेकिन दूसरी ओर, धान की बढ़ती लागत, फसल की अनिश्चितता और नमीयुक्त फसल के कारण निर्यातकों के मुनाफे पर भारी दबाव बन आया है। निर्यातकों का कहना है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय चावल की कीमतें बनाए रखना और प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखना इस समय एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

इन तमाम चुनौतियों के बीच देश का सुरक्षित और केंद्रीय सरकारी भंडार फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में है, जो किसी भी आपात स्थिति या खाद्य संकट से निपटने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उपभोक्ता मामलों और खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक उपलब्ध है, जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम बफर स्टॉक के मानकों से कई गुना अधिक है। अल नीनो और मानसून की अनियमितता ने कृषि क्षेत्र के सामने एक गंभीर चेतावनी पेश कर दी है, जिससे धान के साथ-साथ आगामी रबी सीजन की अन्य फसलों जैसे गेहूं, सरसों और चने की बुआई पर भी आंशिक संकट पैदा हुआ है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में गिरावट और जलाशयों में पानी की कमी के कारण सिंचाई को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। हालांकि, भारत की मजबूत कृषि बुनियाद, किसानों का अथक परिश्रम और सरकार के पास उपलब्ध विशाल बफर स्टॉक इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि देश किसी भी बड़े खाद्य संकट से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। आवश्यकता इस बात की है कि बदलते मौसम के मिज़ाज को ध्यान में रखते हुए कृषि रणनीतियों में समय रहते बदलाव किए जाएं।

विचार

मक्का पैक्ट से भारत की घेराबंदी की कोशिश

पुष्परंजन

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान तुर्किये के अंताल्या में हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (सीओपी31) के शिखर सम्मेलन में उनका आना एक औपचारिकता और रस्मों-उल्फत निभाने जैसा नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) का 31वां वार्षिक सत्र है। इस सम्मेलन की मेज़बानी तुर्किये कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य मकसद वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों की समीक्षा करना है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जलवायु वार्ता में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। एर्दोआन से रिश्ते बेहतर होते, तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन ने मंगलवार को तुर्किये के अंताल्या में बांग्लादेश से संबंधों को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक की। लगभग 30 मिनट की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. खलीलुर रहमान और विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कोबीर भी मौजूद थे। विदेश सचिव सलाहुद्दीन नोमान चौधरी ने बताया कि बांग्लादेश की मुख्य प्राथमिकताओं में अनुकूलन के लिए वित्त जुटाना, नुकसान और क्षति के मुद्दों को संबोधित करना और विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के लिए किए गए वादों को प्रभावी ढंग से लागू कराना शामिल है। विदेश सचिव ने बताया कि सम्मेलन के दौरान जूट उत्पादों के उपयोग और प्रचार-प्रसार को लेकर बांग्लादेश और तुर्किये के बीच एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। लेकिन, असली कार्ड अभी खोला नहीं गया है। क्या बांग्लादेश, 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' का हिस्सा बनना चाहता है? मक्का संयुक्त रक्षा समझौता सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच 7 अगस्त, 2026 को मक्का में हुआ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है। नाटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर किए गए समझौते पर गौर कीजिए, जिसके अनुसार—'तीनों देशों (सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये) में से किसी एक पर भी किया गया सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा।' मक्का समझौते के तहत तीनों देश आपस में खुफिया जानकारी साझा करेंगे, रक्षा उत्पादन और हथियारों के निर्माण में एक-दूसरे की मदद करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से काम करेंगे।

मक्का पैक्ट में यदि बांग्लादेश शामिल होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में ढाका को इस्लामाबाद का पक्ष लेना होगा। यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने पिछले दिनों संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था, 'हम इस पैक्ट को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं।' जब बांग्लादेशी नेताओं और राजनयिकों के कमेंट्स के हवाले से पूछा गया, तो भारत ने कहा कि इस पैक्ट का उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा और वह हालात पर करीब से नजर रख रहा है। हालांकि, बांग्लादेश का इसमें शामिल होने का कोई भी कदम भारतीय सहयोग को मुश्किल बना सकता है। दोनों देशों के बीच 4,096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और उनके बीच मजबूत सांस्कृतिक-आर्थिक रिश्ते हैं। इन रिश्तों में कैसे दरार आए, इसका प्रयास एर्दोआन पाकिस्तान के सहयोग से करने लगे हैं। ढाका में नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर नवीन मुर्शिद की धारणा है कि मक्का एग्रीमेंट के जरिए बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ने में पाकिस्तान की दिलचस्पी भौगोलिक और राजनीतिक वजहों से है। उन्होंने कहा, 'भारत के लिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उसकी पूर्वी सीमा की सुरक्षा जरूरी बातें हैं।' उन्होंने भारत के अपने उत्तर-पूर्वी राज्यों से पतले जमीनी संपर्क का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर में बांग्लादेश उसे घेरे हुए है। उन्होंने समझाया कि ऐसे हालात में बांग्लादेश को साफ तौर पर यह तय करना होगा कि वह इस अलायंस में शामिल होकर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। लेकिन, ढाका में रहने वाले पूर्व राजनयिक एम. हुमायूं कबीर को बांग्लादेश के इस समझौते में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिखता। उनकी टिप्पणी थी, 'बांग्लादेश पिछले 50 से 55 वर्षों में किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि आज भी यह रुख बदला नहीं है। क्या वास्तव में पूर्व राजनयिक एम. हुमायूं कबीर जो सोच रहे हैं, वह सही है? ऐसा लगता नहीं। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों के बाद, एर्दोआन प्रशासन ने ढाका के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत किया है। बांग्लादेश ने तुर्किये से सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिनमें बायराक्तार टीबी-2 ड्रोन, टीआरजी-300 मिसाइल सिस्टम, कोबरा बख्तरबंद वाहन और बोरान होवित्जर तोपें शामिल हैं। इसके साथ ही, दोनों देश रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक सहयोग पर भी काम कर रहे हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अंताल्या में हुई मुलाकात को औपचारिक मत मानिए। इस दौरान उन्होंने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

एक नजर

62 किलो चांदी लूटकांड में पश्चिम बंगाल के दो और गिरफ्तार, डस्टर कार जब्त

दरभंगा,एजेंसी। जिले के सिंहवाड़ा क्षेत्र में शोभन-एकमी बाईपास पर दरभंगा एम्स के समीप पश्चिम बंगाल के सराफा व्यवसायियों से हुई 62 किलो चांदी लूटकांड में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से पश्चिम बंगाल नंबर की डस्टर कार भी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपितों में पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दासपुर थाना क्षेत्र के उदयचौक निवासी मैदुल मलिक (39) तथा गरबेता थाना क्षेत्र के अवुसाबंदी निवासी कौशिक पालुई (22) है। सिमरी थाना पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इनमें दो की संलिप्तता सामने आने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि मोहम्मद महफूजुल्लाह मलिक और शिव शंकर मन्ना को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपित घटना के दिन डस्टर कार से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी और मधेपुर सहित विभिन्न इलाकों से चांदी एकत्र कर पश्चिम बंगाल लौट रहे थे। दोनों लंबे समय से शिव शंकर मन्ना के लिए काम करते थे। मन्ना की पश्चिम बंगाल के दासपुर थाना क्षेत्र के बैकठपुर में सराफा निर्माण की दुकान है। पुलिस ने बताया कि जब्त चांदी के संबंध में अब तक कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब्त डस्टर कार का नंबर डब्ल्यूबी08सी8118 है। विदित हो कि 7 नवंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच शोभन-एकमी बाईपास पर बदमाशों ने पश्चिम बंगाल नंबर की सिल्वर रंग की डस्टर कार को दो बाइक से घेरकर गोलीबारी की थी। इसमें कार चला रहे चालक सह पार्टनर कौशिक के हाथ में गोली लगी थी। इसके बाद बदमाश चांदी के बिस्कुट से भरा बैग और बोरा सहित नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में भाजपा नगर महामंत्री विशाल महासेठ उर्फ विक्की समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 62 किलो 40 ग्राम चांदी के 56 बिस्कुट, 5 लाख 94 हजार 100 रुपये नकद, पांच मोबाइल और दो कार बरामद की गई थीं। पुलिस के अनुसार, लूटकांड की साजिश में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश जारी है।

छठ घाटों का निरीक्षण कर डीएम ने लिया तैयारियों का जायजा, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश



बक्सर। छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने डुमरांव अनुमंडल के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने छठिया पोखरा, डुमरांव रेलवे स्टेशन तथा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर परिसर स्थित छठ घाटों सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों की साफ-सफाई, पहुंच पथ, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ महापर्व से पहले सभी तैयारियां हर हाल में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने विशेष रूप से खतरनाक एवं गहरे पानी वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां बैरिकेडिंग कराने और लाल झंडे लगाने का निर्देश दिया। साथ ही घाटों पर पर्याप्त रोशनी, साफ-सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और घाटों पर लगातार निगरानी रखें। निरीक्षण के दौरान सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, एसडीएम डुमरांव सहित नगर परिषद डुमरांव एवं नगर पंचायत ब्रह्मपुर के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद रहे।

भास्कर महोत्सव के तहत तीन दिवसीय भोजपुरी चित्रकला प्रशिक्षण शुरू, 13 नवंबर को लगेगी प्रदर्शनी

बक्सर। भास्कर महोत्सव 2026 के अवसर पर बुधवार को आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, बक्सर में तीन दिवसीय निःशुल्क भोजपुरी चित्रकला प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार तथा जिला प्रशासन बक्सर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त श्रीमती निहारिका छवि ने किया। प्रशिक्षण शिविर 11 से 13 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों कृष्णा, अभिमन्यु, प्रभात, राहुल, सत्यम एवं रत्न मानस द्वारा छठ महापर्व के पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति से हुई। वहीं, उच्च विद्यालय जासो के छात्र-छात्राओं ने छठ गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने बच्चों को छठ महापर्व की महत्ता, लोक संस्कृति की समृद्ध परंपरा और कला के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा निखारने तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के बीच चित्रकला सामग्री का वितरण भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 13 नवंबर को अपराह्न 2:30 बजे रामरेखा घाट स्थित लाइट एंड साउंड परिसर में होगा। इस अवसर पर कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

अतिक्रमण की अभी कोई पुष्टि नहीं: प्रभारी सीओ आलोक कुमार

दरभंगा। जिले के अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर से जुड़े पोखरभिंडा गांव के जमीन विवाद में प्रशासन ने अभी अतिक्रमण की पुष्टि नहीं की है। तारडीह प्रखंड के प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जब तक मामले की विधिवत जांच और जमीन की मापी नहीं हो जाती, तब तक अतिक्रमण को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को सुनकर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि कुछ ग्रामीणों ने विधायक के परिवार से संबंधित जमीन को लेकर सार्वजनिक सड़क, सामूहिक श्राद्धस्थल, नाले और निजी रैयती भूमि पर कथित अतिक्रमण की शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं के आवेदन को मीडिया में प्रमुखता मिलने के बाद मामला चर्चा में आया। हालांकि, आवेदन में लगाए गए आरोपों की अभी प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। इधर, विधायक मैथिली ठाकुर के करीबी लोगों का कहना है कि पोखरभिंडा में प्रस्तावित भवन का उद्देश्य निजी सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र की जनता के बीच उपलब्ध रहना और विकास योजनाओं की समीक्षा, जनसमस्याओं पर बैठक तथा अन्य जनहितकारी गतिविधियों को संचालित करना है।

छठ घाटों के निरीक्षण में गायब मिले अधिकारी-कर्मी, डीएम ने रोका वेतन

सीवान। छठ महापर्व को लेकर घाटों की साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंगलवार को विभिन्न छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान कई प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी अपने निर्धारित स्थल से गायब मिले। वहीं, कुछ कर्मियों द्वारा जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी लापरवाही बरती जा रही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। सहायक निदेशक, दिव्यांगजन कोषांग रूपेश कुमार निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले। उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए अगले आदेश तक निरीक्षण वाले दिन का वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं, नगर परिषद सीवान के सिटी मैनेजर बलेश्वर राय के खिलाफ भी अनधिकृत अनुपस्थिति को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए वेतन स्थगित करने की कार्रवाई की गई है। नगर परिषद के चार अन्य कर्मियों से भी जवाब-तलब किया गया है। इनमें कमीशन कर संग्रहकर्ता बिपिन कुमार और अनिल कुमार, दैनिक पारिश्रमिक कर्मी सरफराज अली तथा वार्ड जमादार प्रिंस कुमार शामिल हैं। इन सभी से पूछा गया है कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने और अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण क्यों नहीं उनका अनुबंध रद्द कर दिया जाए। घाटों की विशेष



साफ-सफाई के लिए पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सफाई कर्मी उपलब्ध नहीं कराने पर नगर परिषद ने तीन आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सर्जिकल सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा टेक्नो फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। तीनों एजेंसियों को तत्काल पर्याप्त सफाई कर्मी उपलब्ध कराने और निर्धारित समय-सीमा में प्रमुख छठ घाटों की विशेष साफ-सफाई पूरी कराने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर एजेंसियों के मासिक विपत्र से राशि काटने की चेतावनी दी गई है। साथ ही, संविदा की शर्तों के तहत अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि छठ महापर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर घाटों की स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों और सेवा प्रदाता एजेंसियों को पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पर्व के दौरान व्यवस्था में लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुत्र की ''फ्लॉप राजनीति'' से हताश हैं सोनिया गांधी, नीतीश कुमार पर अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं : उमेश सिंह कुशवाहा

पटना। बिहार जनता दल यूनाईटेड(जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बुधवार को इसे सोनिया गांधी का ''राजनीतिक दिवालियापन'' करार देते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि बेदाग छवि वाले युगपुरुष नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के ''राजनीतिक प्रमाणपत्र'' की आवश्यकता नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का चार दशकों से भी अधिक का राजनीतिक और सामाजिक जीवन सादगी, सौम्यता, शालीनता और शुचिता की मिसाल रहा है।

लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार का एक आने का भी आरोप नहीं लगा है। इसके विपरीत, सोनिया गांधी का परिवार आज देश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद इतना विराट और बेदाग है कि उनके व्यक्तित्व पर छींटाकशी करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस के किसी भी नेता के पास नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अपने ''राजनीतिक वारिस'' की बारंबार विफल हो रही ''लॉन्चिंग'' से सोनिया गांधी भारी कुंठा और बौखलाहट से ग्रस्त हैं। अपनी दलगत विफलताओं और जनाधार-विहीन होते नेतृत्व पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर अनर्गल आरोप गढ़ना अब कांग्रेस की राजनीतिक फितरत बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे युगपुरुष पर अनर्गल टीका-टिप्पणी बिहार और देश की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी और इसका राजनीतिक खामियाजा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज राजनीतिक रसातल में जा रही है, तो इसका एकमात्र कारण गांधी परिवार का एकाधिकारवादी रवैया है। देश भर में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से सिमट चुका है। यदि पार्टी का यही अलोकतांत्रिक और अमर्यादित राजनीतिक आचरण जारी रहा, तो आगामी समय में कांग्रेस केवल इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाएगी।

सामाजिक समरसता और पारस्परिक सद्भाव ही समाज की असली ताकत : नीतीश कुमार



पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को गर्दनीबाग स्थित ठाकुरबाड़ी, रोड नंबर-12 में आयोजित भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की पूजा में शामिल हुए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान चित्रगुप्त के प्रति श्रद्धा निवेदित की और प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और पारस्परिक सम्मान किसी भी समाज की बुनियादी ताकत हैं। बिहार की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साझा सामाजिक परंपराओं से रही है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए समाज के सभी वर्गों के बीच प्रेम, विश्वास और भाईचारे को मजबूत करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हमारी परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करते हैं। सामाजिक समरसता के लिए आयोजित प्रीतिभोज जैसी पहलें जाति और वर्ग के भेद से ऊपर उठकर एक साथ बैठने, सहभागिता और आत्मीयता का संदेश देती हैं। समाज में सद्भाव और सहयोग का वातावरण बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्यों और अन्य गणमान्य लोगों ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से आत्मीय मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता एवं विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक कुमार उपस्थित थे।

पांच साल से अधूरा प्लेटफार्म नंबर पांच का निर्माण शीघ्र पूरा करने का निर्देश, एवीटीएम से टिकट निकालकर परखी व्यवस्था

सीवान,एजेंसी। छठ महापर्व पर यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने भटनी-छपरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीवान जंक्शन पहुंचकर यात्री सुविधाओं, संरक्षा व्यवस्था और स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की। पांच वर्षों से निर्माणाधीन प्लेटफार्म संख्या पांच का काम अब तक पूरा नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जतायी और संबंधित अधिकारियों को निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। अपर महाप्रबंधक ने अपर मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) अशोक कुमार वर्मा के साथ रेलखंड का निरीक्षण करते हुए रेलवे ट्रैक, रेलपथ अनुरक्षण, सिग्नल व्यवस्था, समपार फाटकों, पुल-पुलियों, ओवरहेड विद्युत उपकरणों और स्टेशन यार्ड की स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने संरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीवान जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लेटफार्म, यात्री आश्रय केंद्र, टिकट काउंटर, प्रवेश एवं निकास मार्ग, फुट ओवरब्रिज, लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ियों, प्रतीक्षालय, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था की पड़ताल की। इस दौरान प्लेटफार्म संख्या पांच का निर्माण लंबे समय से अधूरा रहने का मामला सामने आया। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने और इसे जल्द पूरा कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान अपर



महाप्रबंधक ने एटीवीएम मशीनों की कार्यप्रणाली भी परखी। उन्होंने स्वयं एक मशीन से टिकट निकालकर व्यवस्था देखी। वहीं, दूसरी मशीन से टिकट निकालने में विलंब होने पर संबंधित वेंडर को फटकार लगायी। उन्होंने मशीनों के सुचारु संचालन और यात्रियों को टिकट लेने में अनावश्यक परेशानी नहीं होने देने का निर्देश दिया। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए उन्होंने स्टेशन पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, यात्रियों के व्यवस्थित आवागमन, हेल्प डेस्क, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा और ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान की नियमित उद्घोषणा सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने पर जोर दिया। अपर महाप्रबंधक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि छठ के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और स्टेशन पर तैनात कर्मचारी यात्रियों की सहायता के लिए तत्पर रहें। निरीक्षण के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक अशोक कुमार वर्मा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ऑपरेशन) अजय कुमार, मंडल वाणिज्य प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव, मंडल संरक्षा अधिकारी अभिषेक कुमार, सहायक मंडल विद्युत अभियंता गोपाल दास गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे।

24 घंटे में दूसरी बार पुलिस टीम पर अपराधियों का हमला, अवर निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मी घायल



नवादा,एजेंसी। अपराधियों और माफियाओं का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी कार्रवाई करने पहुंची टीमों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मंगलवार को बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर हमला किया था, तो बुधवार को वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोधीपुर गांव में छापेमारी करने पहुंची साइबर थाना की पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस घटना में एसआइ रंजन कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गये. जख्मी पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए पावापुरी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, साइबर थाना की पुलिस टीम साइबर ठगी के मामले में आरोपितों की तलाश में सोधीपुर गांव पहुंची थी। पुलिस टीम गांव में छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया गया. अचानक हुए हमले में एसआइ रंजन कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आयीं। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की पुष्टि साइबर डीएसपी मो. शाहनवाज अख्तर ने की है। उन्होंने बताया कि हमले में जख्मी पुलिसकर्मियों का इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल एसआइ रंजन कुमार की हालत ठीक बतायी जा रही है। हालांकि, हमले के दौरान कितने लोग शामिल थे और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आयी है। नवादा में दो दिनों के भीतर सरकारी कार्रवाई करने पहुंची टीमों पर हमले की यह दूसरी घटना है। मंगलवार को गोविंदपुर थाना क्षेत्र के करणपुर बालू घाट स्थित सकरी नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया था। इस घटना में खान निरीक्षक संतोष प्रकाश झा, खान निरीक्षक सौरभ अभिषेक और एक होमगार्ड जवान घायल हो गये थे। खान निरीक्षक संतोष प्रकाश झा को सबसे अधिक चोटें आयी थीं। अब अगले ही दिन साइबर थाना की पुलिस टीम को निशाना बनाया गया है। साइबर ठगी से लेकर अवैध बालू खनन तक के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकारी टीमों पर लगातार हो रहे हमलों ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं। आखिर अपराधियों और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के मन में कानून का भय क्यों नहीं दिख रहा है।

छठ पूजा पर रेलवे का तोहफा : पांच जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा एनएफआर, कई ट्रेनों के फेरे व कोच भी बढ़े

कटिहार। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के विभिन्न मार्गों पर कुल पांच जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इसके तहत दो जोड़ी ट्रेनों की सेवा का विस्तार किया गया है, जबकि तीन अतिरिक्त जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने दी।

सीपीआरओ श्री शर्मा ने बताया कि विस्तारित सेवाओं के अंतर्गत कटिहार-पूर्णिया के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 07555/07554 का मार्ग बढ़ाकर अब अररिया तक कर दिया गया है। आठ कोच वाली यह ट्रेन 11 से 30 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन रात 21:30 बजे कटिहार से खुलकर 23:30 बजे अररिया पहुंचेगी, जबकि वापसी में 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक अररिया से 00:15 बजे खुलकर 02:15 बजे कटिहार आएगी। प्रत्येक दिशा में 20 फेरे लगाने वाली इस ट्रेन के अलावा रांची-अलीपुरद्वार जंक्शन साप्ताहिक पूजा स्पेशल (08661/08662) के दो-दो अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं। यह ट्रेन रांची से 16 व 23 नवंबर को और अलीपुरद्वार जंक्शन से 18 व 25 नवंबर को अपने मौजूदा समय और ठहराव के अनुसार संचालित होगी। रेलवे ने स्थानीय श्रद्धालुओं और व्रतियों की सुविधा के लिए कटिहार-मनिहारी रेलखंड पर विशेष व्यवस्था करते हुए दो जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत आठ कोच वाली ट्रेन संख्या 07546/07545 दैनिक स्पेशल 9 से 16 नवंबर तक कटिहार से रात 23:15 बजे रवाना होकर 00:15 बजे मनिहारी पहुंच रही है और वापसी में 10 से 17 नवंबर तक मनिहारी से 02:00 बजे चलकर 03:00 बजे कटिहार पहुंचेगी। इसी मार्ग पर ट्रेन संख्या 07548/07547 फेस्टिवल स्पेशल 11 से 16 नवंबर तक प्रतिदिन कटिहार से सुबह 10:45 बजे खुलकर 11:45 बजे मनिहारी जाएगी तथा वापसी में 12:00 बजे मनिहारी से चलकर 13:00 बजे कटिहार लौटेगी। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रेन संख्या 07540/07539 (कटिहार-मनिहारी-कटिहार) फेस्टिवल स्पेशल में तीन अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 22 कोच वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 03125/03126 (कोलकाता-न्यू कोचबिहार-कोलकाता) भी चार-चार फेरों के लिए चलाई जा रही है। आगामी 14, 21 और 28 नवंबर को ट्रेन संख्या 03125 कोलकाता से रात 23:40 बजे रवाना होकर अगले दिन 15:30 बजे न्यू कोचबिहार पहुंचेगी, जबकि वापसी में 15, 22 और 29 नवंबर को ट्रेन संख्या 03126 न्यू कोचबिहार से शाम 18:30 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 08:10 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

एक नजर

अंडर-12 अवस्थी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट : एमपीएस ने पारकर को छह विकेट से हराया



मुरादाबाद। अंडर-12 अवस्थी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में एमपीएस क्रिकेट एकेडमी ने पारकर क्रिकेट एकेडमी को छह विकेट से पराजित कर दिया। एमपीएस एकेडमी के तेजस मैन ऑफ द मैच बने। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद के सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने बताया कि दिल्ली रोड स्थित एमपीएस क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर आयोजित टूर्नामेंट में बुधवार को खेले गए मैच में बल्लेबाजी करने उतरी पारकर की टीम 27.4 ओवर में 103 रन बनाकर आउट हो गई। इसमें काव्यांश ने 27, अकबर ने 23, नीरज ने 18, अंजर ने 40, दक्ष ने 19 रन बनाए। एमपीएस की ओर से तेजस ने तीन, माध्विक और आयुष ने दो-दो तथा अब्दुल और कृष्णा ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए एमपीएस एकेडमी ने 17 ओवर में चार विकेट पर 105 रन बनाकर जीत दर्ज की। अनंत ने 27, अर्श ने नाबाद 24, समर्थ ने नाबाद 12, दिव्यांश ने 30 और अरबाज ने आठ रन बनाए। पारकर एकेडमी की ओर से प्रतीक ने दो और रुद्राक्ष ने एक विकेट लिया। तीन विकेट लेने पर तेजस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें कोच मोहम्मद सलीम ने पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान अवस्थी मेमोरियल कमेटी के सचिव नितिन गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव साउद आलम, मिर्जा दानिश आलम, प्रतीक्षा, हिमांशु आदि मौजूद रहे।

युवा ओलंपिकः मुक्केबाज अंबेकर मीतेई 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंचे, भारत का एक और पदक पक्का



डकार (सेनेगल)। भारतीय मुक्केबाज लैरेनलाकपम अंबेकर मीतेई ने बुधवार को 2026 समर यूथ ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 50 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कोलंबिया के इज्जोन जेफरी गालेया अरेवालो को 5-0 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत का मुक्केबाजी में एक और पदक सुनिश्चित हो गया। रेड कॉर्नर से उतरे मीतेई ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। पांचों जजों ने उन्हें विजेता घोषित किया। मुकाबले में जजों के स्कोर 28-27, 28-27, 28-27, 29-26 और 28-27 रहे। फाइनल में मीतेई का सामना आयरलैंड के क्रिस्टियन जुबानी से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में मेक्सिको के एलन जीसस ओकाम्पो कानो को 5-0 से शिकस्त दी। मीतेई ने क्वार्टर फाइनल में सेनेगल के फाये शेख इब्राहिमा फॉल को 5-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी। इससे पहले उन्होंने पहले दौर में नामीबिया के अब्राहम कालेंगा को एक मिनट 57 सेकंड में रेफरी द्वारा मुकाबला रोके जाने (आरएससी) के आधार पर पराजित किया था। इस जीत के साथ ही उन्होंने भारत के लिए कम से कम कांस्य पदक पक्का कर दिया था। यूथ ओलंपिक की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत का यह दूसरा पदक सुनिश्चित हुआ है। इससे पहले महिला 48 किलोग्राम वर्ग में गुंजन ने मेक्सिको की एटेना सोफिया जुआरेज कैलरो को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और देश के लिए पदक पक्का किया था।

नीरज कुमार ने विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य, भारत को ओलंपिक कोटा भी दिलाया



दोहा। भारतीय निशानेबाज नीरज कुमार ने बुधवार को कतर के दोहा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप (राइफल, पिस्टल और शॉटगन) में कांस्य पदक जीतकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में भारत के लिए लॉस एंजिलिस ओलंपिक-2028 का कोटा भी हासिल किया। नीरज मुकाबले में शीर्ष दो स्थानों पर जगह बनाने की राह पर थे, लेकिन अंतिम निशाने पर 9.7 अंक हासिल करने के कारण उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।

उन्होंने कुल 346.5 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। चेक गणराज्य के पैट्रिक यानी 357.2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि स्वर्ण पदक रूस के दिमित्री पिमेनोव ने जीता। पिमेनोव ने 362.8 अंक हासिल करते हुए जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारत के एक अन्य निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर पांचवें स्थान पर रहे। वह भी ओलंपिक कोटा हासिल करने के करीब पहुंचे, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे पैट्रिक यानी पहले ही एक अन्य स्पर्धा में कोटा हासिल कर चुके थे। इस कारण इस स्पर्धा का कोटा नीरज के नाम रहा। नीरज और ऐश्वर्य के संयुक्त प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इस स्पर्धा में टीम कांस्य पदक भी हासिल किया। भारत ने इससे पहले 2023 में बाकू में टीम स्वर्ण और 2022 में काहिरा में टीम कांस्य पदक जीता था।

रहमत शाह ने रचा इतिहास, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी बने

नई दिल्ली,एजेंसी। अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंकिंग हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह अफगानिस्तान के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट बल्लेबाजी या गेंदबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शारजाह में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में करियर का सर्वश्रेष्ठ 173 रन बनाने के बाद उन्हें यह उपलब्धि मिली। उनके अब 735 रेटिंग अंक हो गए हैं, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा था। दोनों टीमों ने अपनी-अपनी पारियों में 500 से अधिक रन बनाए थे। इस मुकाबले में शतक लगाने वाले अफगानिस्तान के अन्य बल्लेबाजों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। 105 रन बनाने वाले सेदिकुल्लाह अटल 14 स्थान ऊपर चढ़कर 81वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 414 रेटिंग अंक भी करियर के सर्वश्रेष्ठ हैं। वहीं, पदार्पण टेस्ट की पहली पारी में 113 रन बनाने वाले रहमानुल्लाह संयुक्त रूप से 83वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की भी लंबी छलांग

जिम्बाब्वे ने एक ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 500 से अधिक रन बनाकर इतिहास रचा। टीम के बल्लेबाजों को इसका फायदा आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है। 41 वर्ष और 84 दिन की उम्र में टेस्ट दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने क्रेग इरविन नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रायन बेनेट ने 128 और 58 रन की पारियां खेलीं, जिसके बाद वह 10 स्थान की छलांग लगाकर 75वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं, 131 और 82 रन बनाने वाले ब्रेंडन टेलर 29 स्थान ऊपर चढ़कर 103वें स्थान



पर पहुंच गए हैं। वेस्ली मधेवेरे ने भी अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष 100 में पहली बार जगह बनाई है। वह अब 99वें स्थान पर हैं।

तौहीद हृदोय को 115 स्थान का फायदा

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच सिलहट में खेला गया आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का दूसरा मुकाबला भी ड्रॉ रहा। हालांकि, पहले टेस्ट में आठ विकेट से जीत दर्ज करने के कारण वेस्टइंडीज ने सीरीज अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के बल्लेबाज तौहीद हृदोय को रैंकिंग में सबसे बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने पहली पारी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के तौर पर नाबाद 242 रन बनाए और दूसरी पारी में 82 रन की पारी खेली। इसके बाद वह 175वें स्थान से सीधे 60वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कावेम हॉज ने दूसरी पारी में 142 रन बनाए और अपनी टीम को बांग्लादेश के सामने 369 रन का लक्ष्य रखने में मदद की। वह करियर की सर्वश्रेष्ठ 52वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। उनके साथी अमीर जांगू ने भी टेस्ट क्रिकेट में शानदार शुरुआत जारी रखी है। पहली पारी में 133 रन बनाने के बाद वह 28 स्थान ऊपर चढ़कर 62वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

वारिकन पहली बार शीर्ष 20 में शामिल

बल्लेबाजों के दबदबे वाले इन मुकाबलों में गेंदबाजों को रैंकिंग में ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए वारिकन ने सिलहट टेस्ट में सात विकेट लिए। इसके बाद वह 11 स्थान ऊपर चढ़कर टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में संयुक्त रूप से 19वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह पहली बार है, जब उन्होंने शीर्ष 20 में जगह बनाई है। ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी वह चार स्थान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के उनके साथी जस्टिन ग्रीव्स को भी ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक स्थान का फायदा हुआ है। वह संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने वेस्टइंडीज की पहली पारी में 90 रन देकर छह विकेट लिए थे। इसके बाद वह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में छह स्थान ऊपर चढ़कर 32वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जिम्बाब्वे के न्यूमैन न्यामहुरी ने अफगानिस्तान की 514 रन की पारी के दौरान 82 रन देकर पांच विकेट लिए थे। वह 10 स्थान ऊपर चढ़कर करियर की सर्वश्रेष्ठ 75वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।

एकदिवसीय रैंकिंग में गिल शीर्ष पर बरकरार

न्यूजीलैंड और भारत के बीच जारी एकदिवसीय सीरीज पर बारिश का असर पड़ने के कारण खिलाड़ियों को रैंकिंग में बड़े बदलाव का मौका नहीं मिला। मंगलवार को हैमिल्टन में तीसरा एकदिवसीय मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। आईसीसी पुरुष एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष चार स्थानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत के शुभमन गिल पहले स्थान पर कायम हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे, भारत के विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। भारत के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में 23 स्थान का फायदा हुआ है। वेलिंगटन में दूसरे मुकाबले में उन्होंने 28 रन देकर दो विकेट लिए थे। इसके बाद वह 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके साथी अर्शदीप सिंह ने भी 11 स्थान की छलांग लगाई है। वह संयुक्त रूप से 31वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑकलैंड में पहले मुकाबले में चार विकेट लेने के बाद वेलिंगटन में किफायती गेंदबाजी की थी। भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने भी एकदिवसीय क्रिकेट में शानदार शुरुआत जारी रखी है। ऑकलैंड में 44 रन देकर तीन और वेलिंगटन में 30 रन देकर चार विकेट लेने के बाद वह 60 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वह अपने शुरुआती 12 एकदिवसीय मुकाबलों में 21 विकेट हासिल कर चुके हैं।

पॉल रीफेल ने अंपायर के रूप में पूरे किए 100 वनडे, आईसीसी ने दी बधाई

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने ऑस्ट्रेलिया के पॉल रीफेल को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर के रूप में 100 मैच पूरे करने पर बधाई दी है। रीफेल ने मंगलवार को न्यूजीलैंड और भारत के बीच हैमिल्टन में खेले गए तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में मैदानी अंपायर की भूमिका निभाते हुए यह उपलब्धि हासिल की।

रीफेल कम से कम 100 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में मैदानी अंपायरिंग करने वाले दुनिया के 23वें अंपायर बन गए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले छठे ऑस्ट्रेलियाई अंपायर हैं। उनसे पहले डैरिल हार्पर, साइमन टॉफेल, डैरेल हेयर, स्टीव डेविस और रॉड टकर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आईसीसी के महाप्रबंधक (आयोजन एवं क्रिकेट संचालन) गौरव सक्सेना ने कहा, 'आईसीसी सौभाग्यशाली है कि उसके पास अंपायरों का एक प्रतिष्ठित पैनल है, जिसके सदस्य पूर्व खिलाड़ी और अधिकारी के रूप में खेल का व्यापक अनुभव और समझ रखते हैं। पॉल इस सफर का एक शानदार उदाहरण हैं। उन्होंने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर पर खेलने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक अंपायरिंग की ओर रुख किया और खुद को खेल के सबसे सम्मानित अधिकारियों में स्थापित किया। आईसीसी के एलीट पैनल में उनके 13 वर्ष उनकी निरंतरता, पेशेवर रवैये और उनके द्वारा बनाए रखे गए उच्च मानकों को दर्शाते हैं।आईसीसी की ओर से मैं पॉल को अंपायर के रूप में 100 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई देता हूं और आने वाले वर्षों में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं। इस उपलब्धि पर पॉल रीफेल ने कहा, 'मैं वर्षों से मिले सहयोग के लिए आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आभारी हूं। साथ ही, एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के अपने साथी अंपायरों और रेफरी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सफर में शानदार साथ दिया और मुझे सलाह दी। मैं अपने परिवार और दोस्तों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और लगातार मेरा समर्थन तथा उत्साहवर्धन करते रहे। खेल के सर्वोच्च स्तर पर पहले क्रिकेटर और फिर अंपायर के रूप में जुड़े रहना एक शानदार सफर रहा है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये अवसर मिले। मैं आने वाले वर्षों में भी कई और मुकाबलों का हिस्सा बनने और अनेक नई यादें बनाने के लिए उत्सुक हूं।'

मप्र के भोपाल में 19 नवंबर से होगा एशियन महिला हॉकी का महासंग्राम, मंत्री सारंग ने लोगो और ट्रॉफी का किया अनावरण

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 से 28 नवंबर तक पहली बार एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल-2026 का आयोजन होगा, जिसमें भारत, जापान, चीन, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की छह शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। प्रदेश के सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में ट्रॉफी के आधिकारिक लोगो और ट्रॉफी अनावरण के साथ ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया।

मंत्री सारंग ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश के लिए यह गौरव और प्रतिष्ठा का विषय है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है। एशियन हॉकी फेडरेशन एवं हॉकी इंडिया के सहयोग से मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 19 से 28 नवंबर 2026 तक अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बरखेड़ा नाथू, भोपाल में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लगभग पांच हजार दर्शकों की क्षमता वाले अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम में दर्शकों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। वर्ल्ड रैंकिंग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की गरिमामयी उपस्थिति में प्रतियोगिता का शुभारंभ एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रथम चरण का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में एशिया की 6 शीर्ष महिला हॉकी टीमें भारत, जापान, चीन, मलेशिया,



कोरिया और थाईलैंड की लगभग 150 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल अधोसंरचना के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भी खेलों के क्षेत्र में तेजी से अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश की खेल क्षमताओं और विश्वस्तरीय आयोजन की तैयारियों का प्रमाण है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय महिला हॉकी टीम मैदान में उतरेगी। शुभारंभ दिवस पर कुल तीन मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। पहला मुकाबला चीन और थाईलैंड के बीच दोपहर 1 बजे, दूसरा मुकाबला जापान और कोरिया के बीच दोपहर 3:15 बजे तथा तीसरा और दिन का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला मेजबान भारत और मलेशिया के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एवं हॉटस्टार पर प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण होगा। प्रतियोगिता के व्यापक प्रचार-प्रसार और आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 11 नवंबर से 17 नवंबर तक ट्रॉफी टूर का आयोजन किया गया है। जो भोपाल से प्रारंभ होकर मध्यप्रदेश के सभी संभागों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में ट्रॉफी टूर किया जाएगा। सभी संभागों में मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधायकगण द्वारा ट्रॉफी का स्वागत किया जाएगा।

बल्लेबाजों के बढ़ते दबदबे पर बोल्ट ने जताई चिंता, ईगल्स ने बुल्स को 25 रनों से हराया

अबूधाबी,एजेंसी। एमिरेट्स ईगल्स ने मंगलवार को अबूधाबी टी10 लीग में डिफेंडिंग चैंपियन यूएई बुल्स को 25 रन से हरा दिया। मैच में ट्रेंट बोल्ट ने दो ओवर में 10 रन देकर एक विकेट लिया। मैच के बाद न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बोल्ट ने कहा कि सफेद गेंद के क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और बल्लेबाजों का दबदबा पहले से कहीं अधिक हो गया है। बोल्ट ने कहा कि अब नई गेंद ज्यादा देर तक स्विंग नहीं होती और दुनिया भर में बड़े स्कोर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'गेंद शायद अब उतनी स्विंग नहीं होती, जितनी पहले हुआ करती थी और आप दुनिया भर में बड़े स्कोर देख रहे हैं। खेल बदल रहा है, नियमों में कुछ बदलाव हुए हैं और मैच देर रात तक खेले जा रहे हैं। आपने एकदिवसीय क्रिकेट में 400 से ज्यादा रन का लक्ष्य हासिल होते देखा है। क्या हमने 10 साल पहले सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं। मुझे नहीं पता कि खेल अब किस दिशा में जाएगा।

अपने करियर में स्विंग गेंदबाजी की भूमिका पर बोल्ट ने कहा, 'मुझे स्विंग गेंदबाजी से प्यार हो गया था। युवा खिलाड़ी उन गेंदबाजों को अपना आदर्श मानते हैं, जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं। इसलिए जब भी मुझे ऐसा करने का मौका मिलता है, मैं उसे दोनों हाथों से पकड़ने और अपने कौशल को दिखाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि मुझे आगे भी ऐसा करने के कुछ और मौके मिलेंगे।



उन्होंने कहा कि अब गेंद बहुत कम समय तक स्विंग होती है और लगातार क्रिकेट खेलने के कारण गेंदबाजों को प्रभावी बने रहने के लिए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। बोल्ट के मुताबिक, 'गेंद केवल उतने समय तक स्विंग होती है, जो बहुत कम लगता है। जब आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको प्रभावी बने रहने और बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। हर बार योजना के मुताबिक चीजें नहीं होतीं लेकिन मुझे अंतिम ओवरों में कुछ अलग तरह की गेंदें डालना और बल्लेबाज से एक कदम आगे रहने की कोशिश करना पसंद है। बोल्ट ने कहा कि टी10 जैसे प्रारूप में गेंदबाजों को अपनी सफलता पर ज्यादा जश्न मनाने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा, 'मैं ज्यादा जश्न मनाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि एक या दो छक्के लगते ही सबकुछ गलत हो सकता है। लेकिन यह 60 गेंदों का खेल है। यहां एक-दो डॉट गेंदें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर हम अंतिम दो या तीन ओवरों तक बल्लेबाजों को जितना संभव हो रोक पाते हैं तो इससे हमें अच्छी स्थिति में पहुंचने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए इस खेल का आनंद लेने का तरीका चेहरे पर मुस्कान के साथ खेलना है। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक यहां दर्शकों के बीच मौजूद था और उसने भी मेरे साथ इस पल का जश्न मनाया। फ्रेंचाइजी क्रिकेट को समझने के सवाल पर बोल्ट ने कहा, 'बिल्कुल नहीं। मेरे कुछ दिन अच्छे रहे हैं और कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं, जब चीजें योजना के मुताबिक नहीं हुईं।

मलखंब प्रतियोगिता में बिजनौर पुलिस का शानदार प्रदर्शन, 11 स्वर्ण पदकों के साथ जीती चल विजयंती शील्ड

बिजनौर। उत्तर प्रदेश पुलिस की 13वीं वार्षिक मलखंब प्रतियोगिता-2026 में बिजनौर पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए जनपद का गौरव बढ़ाया। पुलिस लाइन मुरादाबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिजनौर पुलिस की टीम ने 11 स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा एकल प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीतकर खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया। शानदार प्रदर्शन के आधार पर बिजनौर पुलिस की टीम ने चल-विजयंती शील्ड भी अपने नाम कर ली।



इस उपलब्धि से पुलिस विभाग में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों की सफलता पर पुलिस अधीक्षक के. के. विश्नोई ने बुधवार को उनका उत्साहवर्धन करते हुए सभी पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम, नियमित अभ्यास, अनुशासन और समर्पण बेहद जरूरी है। बिजनौर पुलिस के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि लगन और मेहनत के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और टीम भावना को भी मजबूत बनाती हैं। मलखम्भ जैसे पारंपरिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता, संतुलन और एकाग्रता का परिचायक है। एसपी के.के. विश्नोई ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में भी इसी प्रकार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजनौर पुलिस के खिलाड़ी आने वाली प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर जनपद के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करेंगे। 11 स्वर्ण पदकों, एकल स्पर्धा में स्वर्ण एवं रजत पदक और चल-विजयंती शील्ड की उपलब्धि बिजनौर पुलिस के लिए गौरवपूर्ण रही।

एक नजर

रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी, 145 संस्थाओं और व्यक्तियों को सूची में शामिल करने पर ईयू की सहमति



ब्रुसेल्स,एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के राजनयिकों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई है। नए प्रस्ताव के तहत रूस की वित्तीय व्यवस्था, प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जहाजों के नेटवर्क और दुष्प्रचार अभियानों से जुड़े 145 संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाया जाएगा। ईयू के राजनयिकों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। इन प्रतिबंधों को 16 नवंबर को होने वाली ईयू के विदेश मंत्रियों की बैठक में औपचारिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इन्हें यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे ये कानूनी रूप से प्रभावी हो जाएंगे। प्रस्तावित प्रतिबंध तीन अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत लागू किए जाएंगे। इनमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के जवाब में लागू ईयू का मुख्य प्रतिबंध ढांचा और रूस की कथित हाइब्रिड गतिविधियों से निपटने वाली व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा, साइबर हमलों से संबंधित एक अलग व्यवस्था के तहत भी एक नाम जोड़ा गया है। मुख्य प्रतिबंध सूची में 113 संस्थाओं और व्यक्तियों को शामिल करने पर सहमति बनी है। इनमें 50 रूसी बैंक, रूस के प्रतिबंधित तेल कारोबार और तथाकथित 'शैडो फ्लीट' को मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क, ऊर्जा कंपनियां और रूसी कारोबारी जगत की कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वहीं, हाइब्रिड गतिविधियों से जुड़ी सूची में 31 संस्थाओं और व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, ये विदेशी दखल और जनमत को प्रभावित करने के अभियानों में कथित तौर पर शामिल हैं।

नेतन्याहू का बदला रुख, बोले- इजराइल में 'राष्ट्रीय एकता' सरकार बनाना संभव

यरुशलम,एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश में 'राष्ट्रीय एकता' सरकार का गठन अब भी संभव है। उनका यह बयान संसद (नेसेट) के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन बाद आया है। इससे पहले उन्होंने अपने बिना सरकार बनाने की कोशिशों पर नाराजगी जताई थी और अरब सांसदों पर आतंकवाद का समर्थन करने तथा इजराइल के विनाश की इच्छा रखने का आरोप लगाया था। नेसेट परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने कहा, 'कल मैंने बताया था कि राष्ट्रीय एकता सरकार क्यों जरूरी है। आज मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करना संभव क्यों है।' इस बार उनका अंदाज पिछले दिन के तीखे भाषण से अलग और अपेक्षाकृत नरम था। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइली समाज निर्णायक क्षणों में एकजुट होना जानता है और देश इस समय ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा, 'यह समय की मांग है और देश के बहुमत की इच्छा भी यही है। उन्होंने नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह और पिछले तीन वर्षों से जारी युद्ध के दौरान सैनिकों तथा आम नागरिकों के बीच दिखी एकजुटता का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और संघर्ष किया। नेतन्याहू ने कहा कि वह सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों और अवसरों से परिचित हैं। उन्होंने संभावित गठबंधन सहयोगियों से बातचीत और संपर्क जारी रखने की बात भी कही। इस बीच, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सरकार बनाने का जिम्मा नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को सौंपा है। ऐसे में 'राष्ट्रीय एकता' सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक बातचीत और सत्ता समीकरणों पर सबकी नजरें टिकी हैं।

ईरान ने दुनिया को दिखाई अपनी नई भूमिगत 'मिसाइल सिटी'

तेहरान। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की एयरोस्पेस फोर्स ने एक नए भूमिगत 'मिसाइल सिटी' का अनावरण किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, इस भूमिगत ठिकाने में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ उनके प्रक्षेपण तंत्र भी रखे गए हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुविधा के अनावरण के दौरान ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दोल्लाही और आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसवी मौजूद रहे। हालांकि, रिपोर्ट में इस भूमिगत ठिकाने के स्थान और वहां मौजूद मिसाइलों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेब्बी ने हाल ही में कहा था कि मिसाइलों और ड्रोन के निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाओं को भूमिगत किया जाएगा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में नए 'मिसाइल सिटी' की क्षमता, निर्माण और संचालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

आइसेनकोट ने नेतन्याहू के भाषण को नफरत भरा बताया, अरब पार्टियों ने उन्हें नस्लवादी ठहराया

यरुशलम (इजराइल)। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार रात नई नेसेट (संसद) में तीखा भाषण दिया। उनके भाषण को नई सरकार बनाने जा रहे 'यशार' पार्टी के नेता गादी आइसेनकोट ने 'नफरत से भरा' करार दिया। अरब पार्टियों ने तंज कसते हुए उन्हें नस्लवादी ठहराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने 'राष्ट्रीय एकता सरकार' बनाने का आह्वान किया। साथ ही अरब पार्टियों पर इजराइल को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अपने राजनीतिक विरोधियों को चेतावनी दी कि वे सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर न रहें। द टाइम्स ऑफ इजराइल और द यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, गादी आइसेनकोट ने कहा कि नेतन्याहू का भाषण यह साबित करता है कि वे इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। अरब सांसदों ने कहा कि उनके भाषण ने उन्हें नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए और भी अधिक दृढ़ बना दिया है। पिछले महीने हुए चुनाव में संसदीय बहुमत खोने के बाद और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के आइसेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश सौंपे जाने के बाद नेतन्याहू ने अपने भाषण में वही पुराना अभियान जारी रखा जो उन्होंने चुनाव के दौरान चलाया था। उन्होंने अरब पार्टियों को अवैध ठहराने और उन्हें आतंकवाद का समर्थक बताने की कोशिश की। भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने बार-बार नेतन्याहू को टोका। उन्होंने नेतन्याहू के सहयोगियों के कतर के साथ कथित संबंधों पर जवाब मांगा और 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नरसंहार की जांच के लिए एक सरकारी आयोग गठित करने से इनकार करने पर सवाल उठाए।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में मंगलवार को ग्रैंड ओल्ड पार्टी (रिपब्लिकन) प्रतिनिधि थॉमस मैसी का रक्षा सचिव (बदला पदनाम युद्ध सचिव) पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया। यह मुख्य रूप से ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर था। हाउस ने 211 के मुकाबले 204 वोटों से इस प्रस्ताव को न्यायपालिका समिति के पास भेजने का फैसला किया। इसी के साथ इस प्रस्ताव ने अपना प्रभाव खो दिया। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मैसी अकेले ऐसे रिपब्लिकन हैं जिन्होंने सभी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इसके खिलाफ वोट दिया। मतदान के बाद मैसी ने कहा, 'मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन निराशा जरूर हुई। कांग्रेस के बारे में मेरा आकलन यह है कि ये लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए। बस वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, भले ही ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक फायदा ही क्यों न हो।

केंटकी के रिपब्लिकन मैसी ने सोमवार को कहा था कि वह हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग का कोई और प्रस्ताव नहीं लाएंगे। इस साल की शुरुआत में प्राइमरी चुनाव हारने के बाद वह जनवरी की शुरुआत में रिटायर हो रहे हैं। डेमोक्रेट्स अभी भी इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं, खासकर तब जब जनवरी में दोनों सदनों (हाउस और सीनेट) पर उनका नियंत्रण वापस आ जाएगा। हाउस में अल्पसंख्यक नेता (माइनॉरिटी लीडर) और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट हकीम जेफ़रीज ने कहा, 'यह अंत नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। मैसी ने कहा कि अब वह 'युद्ध शक्तियों' (वॉर पावर्स) से जुड़े एक प्रस्ताव पर मतदान कराने की योजना बना रहे हैं। मैसी ने कहा, 'हम देखेंगे कि वे सभी रिपब्लिकन, जिन्होंने कहा था कि 'अरे, हम युद्ध की वजह से चुनाव हार गए', क्या वे अब भी इसके पक्ष में वोट देते हैं?' महाभियोग प्रस्ताव में हेगसेथ पर कई आरोप लगाए गए थे। इनमें शामिल हैं- कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के साथ युद्ध शुरू करके अपने पद का दुरुपयोग करना, नागरिकों के नुकसान को कम करने के लिए बने कानूनों की अनदेखी करना, कैरेबियन में पेंटागन के बोट हमलों के दौरान गैर-न्यायिक हत्याओं का निर्देश देना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण का आदेश देना और डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली के खिलाफ बदले की कार्रवाई करना। हेगसेथ ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाभियोग की कोशिश की निंदा की और इसे एक 'तमाशा' और 'राजनीतिक दिखावा' बताया। हेगसेथ ने तर्क दिया, 'इनमें से कोई भी गंभीर अपराध या कदाचार नहीं है। ये केवल पक्षपातपूर्ण नीतिगत असहमति हैं, जो उन लोगों की तरफ से आ रही हैं जो हमारी सेना का राजनीतिकरण करना चाहते हैं।' राष्ट्रपति ट्रंप ने महाभियोग की कोशिश का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि यह 'बुरी तरह से फेल हो गई है! अमेरिकी इतिहास में अब तक केवल दो कैबिनेट सचिवों पर महाभियोग चलाया गया है। 1876 में भ्रष्टाचार के एक मामले को लेकर युद्ध सचिव (सेक्रेटरी ऑफ वॉर) विलियम बेलनैप पर महाभियोग चलाया गया था और 2024 में दक्षिणी सीमा को संभालने के तरीके को लेकर होमलैंड सिक्योरिटी सचिव एलेजांद्रो मायोर्कास पर महाभियोग चलाया गया। सीनेट ने बेलनैप को बरी कर दिया, जबकि मायोर्कास के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया गया।



पाकिस्तान का सी-5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्वच्छ बिजली और ऊर्जा सुरक्षा का प्रतीकः शहबाज शरीफ

इस्लामाबाद। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सी-5 (चश्मा-5) परमाणु ऊर्जा संयंत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए स्वच्छ बिजली और ऊर्जा सुरक्षा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को प्रसारित एक कार्यक्रम में यह बात कही। यह कार्यक्रम मियांवाली के पास सी-5 संयंत्र में 'डोम' (गुंबद) लगाने के अवसर पर आयोजित किया गया। डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में इसे पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सी-5 परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता 1,200 मेगावाट होगी और उम्मीद है कि सितंबर 2030 से यहां बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि भले ही यह ढांचा कंक्रीट और स्टील से बना हो, लेकिन यह स्वच्छ, भरोसेमंद और सस्ती बिजली का वादा है। प्रधानमंत्री शहबाज ने याद दिलाया कि जुलाई 2023 में जब वे इस जगह पर शिलान्यास करने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 'किसी का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से अपना भविष्य खुद बनाएगा।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज साढ़े तीन साल से भी कम समय में तय समय से पहले ही डोम अपनी जगह पर लग चुका है।' उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने पाकिस्तान के सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सातवें परमाणु संयंत्र ष्ट-5 के निर्माण में मदद के लिए चीन का भी आभार जताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, 'यह उस दोस्ती का जीता-जागता सबूत है जो कभी नहीं डगमगाई—चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न रहे हों।' उन्होंने कहा, 'हमारे दोनों देशों की दोस्ती को अकसर हिमालय से भी ऊंचा, महासागरों से भी गहरा, शहद से भी मीठा, सोने और हीरे से भी कीमती और स्टील से भी मजबूत बताया जाता है।'



इजराइली संसद में अरेंजमेंट्स कमेटी के गठन को मंजूरी, अरब दलों का प्रभाव घटाने की लिकुड की कोशिश नाकाम

यरुशलम। इजराइल की संसद नेसट ने 63 के मुकाबले 50 मतों से 22 सदस्यीय अरेंजमेंट्स कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी। याशर पार्टी के सांसद रॉय फोकमैन की ओर से पेश प्रस्ताव के तहत गठित इस समिति में गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गुट और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करने वाले गुट को नौ-नौ सीटें मिली हैं, जबकि अरब दलों ज्वाइंट लिस्ट और राम को कुल चार सीटें दी गई हैं। फोकमैन के प्रस्ताव के अनुसार, प्रत्येक संसदीय दल को उसके सांसदों की संख्या के आधार पर हर पांच सांसद पर एक सीट दी गई है। इसके तहत लिकुड को पांच, याशर को चार और बी'याचद, ज्वाइंट लिस्ट, डेमोक्रेट्स तथा राम को दो-दो सीटें मिली हैं। वहीं, इजराइल बेतेनु, ओत्जमा येहुदित, यूनाइटेड टोरा जूडिज्म, शास और रिलीजियस जायनिज्म को एक-एक सीट दी गई।

अरेंजमेंट्स कमेटी का गठन महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थायी संसदीय समितियों के गठन तक उसके पास व्यापक अधिकार रहते हैं। यह समिति अन्य संसदीय समितियों की संरचना तय करती है, जिसे बाद में सांसदों की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। इसके अलावा, यह अस्थायी वित्त समिति और विदेश मामलों एवं रक्षा समिति का गठन भी कर सकती है। हाउस कमेटी के चयन तक संसदीय प्रक्रिया और नेसेट के कामकाज की जिम्मेदारी भी इसी के पास रहती है। यह अस्थायी उपसभापतियों की नियुक्ति भी कर सकती है। लिकुड सांसद ओफिर काट्ज ने समिति में अपने गुट का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अलग प्रस्ताव रखा था। उनके शुरुआती प्रस्ताव में प्रत्येक चार सांसदों पर एक प्रतिनिधि देने की बात थी।

इससे नेतन्याहू समर्थक गुट को 15, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले गुट को 12 और अरब दलों को चार सीटें मिलतीं। हालांकि, समिति का आकार बड़ा होने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद काट्ज ने अपने गुट को आठ, आइजेनकोट के गुट को सात और अरब दलों को तीन सीटें देने का सुझाव दिया। आलोचकों ने इसे भेदभावपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि इससे समिति में नेतन्याहू समर्थक गुट को अनुचित बढ़त मिलती।

इजराइल में न्यायिक बदलावों को पलटने की तैयारी, आइजेनकोट गुट बनाएगा विशेष संसदीय समितियां

यरुशलम। इजराइल में गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले राजनीतिक गुट ने पिछली बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक बदलावों से जुड़े कानूनों को रद्द करने के लिए विशेष संसदीय समितियां गठित करने पर सहमति जताई है। हिब्रू मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इन समितियों की जिम्मेदारी न्यायिक व्यवस्था में किए गए विवादित बदलावों को पलटने की दिशा में काम करना होगा। ज्यादातर समितियों की अध्यक्षता यायर गोलान की डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद करेंगे।

ये समितियां नेतन्याहू की निवर्तमान गठबंधन सरकार द्वारा पारित पांच प्रमुख कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पर काम करेंगी। इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में सांसदों की भूमिका बढ़ाने वाला कानून, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने में अटॉर्नी जनरल की भूमिका कमजोर करने वाला प्रावधान और पुलिस के आंतरिक जांच विभाग पर न्याय मंत्री का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाला कानून शामिल है। इसके अलावा, मीडिया और संचार क्षेत्र में व्यापक बदलाव से जुड़े कानून की भी समीक्षा की जाएगी। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। पांचवां कानून प्रधानमंत्री को पद संभालने में अक्षम घोषित किए जाने की परिस्थितियों को सीमित करता है। इसे व्यापक रूप से नेतन्याहू को उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के कारण पद से हटाए जाने की आशंका से बचाने की कोशिश के तौर पर देखा गया है। इनमें से कुछ कानूनों के प्रावधानों पर इजराइल के उच्च न्यायालय ने पहले ही रोक लगा रखी है। पुलिस जांच विभाग और संचार क्षेत्र से जुड़े कानूनों के अहम प्रावधानों का क्रियान्वयन फिलहाल स्थगित है। वहीं, प्रधानमंत्री को पद के लिए अक्षम घोषित करने से संबंधित कानून को 26वीं नेसेट के गठन तक लागू नहीं करने का फैसला किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और अटॉर्नी जनरल की शक्तियों से जुड़े कानूनों को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आइजेनकोट गुट की ओर से विशेष समितियां गठित करने का फैसला इजराइल में न्यायिक सुधारों को लेकर जारी राजनीतिक और कानूनी बहस को नया मोड़ दे सकता है।



रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में समझौते की उम्मीद, क्षेत्रीय अदला-बदली से मॉस्को का इनकार

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए जारी शांति वार्ता में प्रगति की उम्मीद जताते हुए रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा है कि दोनों देश समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी शांति समझौते के तहत रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रों की अदला-बदली की कोई संभावना नहीं है।

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका और यूक्रेन के साथ हुई बातचीत में रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे मेदिंस्की ने रूसी मीडिया से बातचीत में कहा कि शांति समझौते की दिशा में प्रगति संभव है। उनके मुताबिक, इसका काफी कुछ दारोमदार यूक्रेन, अमेरिका के रुख और यूरोप के रवैये पर निर्भर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने जो लक्ष्य तय किए हैं, उन्हें हासिल किया जाएगा। मेदिंस्की ने बताया कि वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ बनी है। उन्होंने संकेत दिया कि आगे भी बातचीत जारी रखने और बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला-बदली करने पर सहमति बनी है।

क्षेत्रों की अदला-बदली की संभावना नहीं

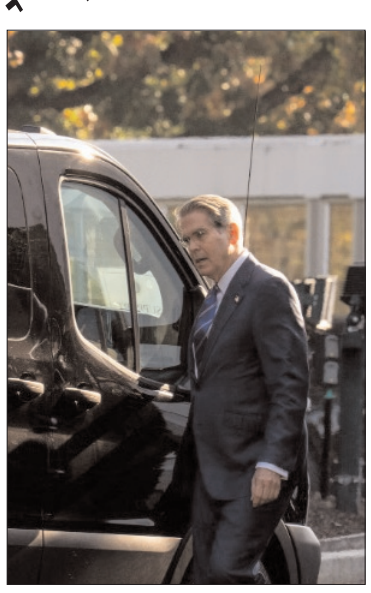
क्षेत्रीय विवाद पर रूसी रुख स्पष्ट करते हुए मेदिंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जमीन की अदला-बदली का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा समय-समय पर विभिन्न पक्षों की ओर से उठाया जाता रहा है, लेकिन रूस की नीति में बदलाव की संभावना नहीं है। मेदिंस्की ने अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना की रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ का हवाला देते हुए कहा कि इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने सीमा पर सुरक्षा क्षेत्र बनाने का फैसला किया था। उनके अनुसार, यह क्षेत्र अब काफी बड़ा हो चुका है और इसका विस्तार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों की अदला-बदली संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सीमा पार अभियान चलाकर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उस समय कहा था कि इस अभियान का उद्देश्य रूस की ओर से यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में होने वाले हमलों से सीमावर्ती आबादी की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। इस अभियान को भविष्य की शांति वार्ताओं में यूक्रेन की सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया था।



ईरान की धमकी के बीच अमेरिकी वित्त सचिव बेसेंट को घर से मिलिट्री बेस ले जाया गया

वाशिंगटन,एजेंसी। ईरान से मिली जान से मारने की धमकी के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक मिलिट्री बेस पर चले गए हैं। यह जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने अपनी पहचान न उजागर करने की शर्त पर यह संवेदनशील जानकारी दी। बताया गया है कि हाल के हफ्तों में अमेरिकी अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ ईरान की साजिशें अब और गंभीर चरण में पहुंच गई हैं। इसमें बेसेंट को मिली धमकी से जुड़ी खुफिया जानकारी भी शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन करते हुए बताया गया है कि अगस्त से बेसेंट एक ऐसे आर्थिक दबाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को कड़े प्रतिबंधों और व्यापार मार्गों पर रोक लगाकर आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है।

इन लोगों के अनुसार, इस भूमिका की वजह से वह प्रशासन के उन अधिकारियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्हें मिली धमकियां कितनी गंभीर हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और विदेश में बड़े पैमाने पर हमले करने की ईरान की क्षमता सीमित है। लेकिन, ईरान की ओर से कुछ खास लोगों को निशाना बनाने की ऐसी धमकी भी मिली हैं जिन्हें अमेरिकी अधिकारी गंभीर मानते हैं। उदाहरण के लिए, 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वह ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने वाले अभियान को जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि बेसेंट ट्रंप प्रशासन के ऐसे नवीनतम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्होंने वाशिंगटन क्षेत्र स्थित अपना घर छोड़कर किसी सैन्य अड्डे या अन्य सुरक्षित आवास में जाना चुना है। पिछले साल कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों ने ऐसा ही किया था। इनमें स्टीफन मिलर (जो अब व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं) और पैम बॉन्डी (जो उस समय अटॉर्नी जनरल थीं) शामिल हैं।



एक नजर

अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली,एजेंसी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14,41,978.91 करोड़ रुपये (करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गया है। आयकर विभाग ने बुधवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्य का 53 फीसदी है। इस दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह भी 18 फीसदी बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं, व्यक्तिगत करदाताओं, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) से प्राप्त शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह 5.3 प्रतिशत बढ़कर करीब 7.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से प्राप्त संग्रह 52 फीसदी बढ़कर 54,078 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि में करदाताओं को जारी किए गए रिफंड में सालाना आधार पर 26 फीसदी की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये रहा। आयकर विभाग ने कहा कि सकल आधार पर प्रत्यक्ष कर संग्रह 14 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें सकल कॉरपोरेट कर संग्रह 8.01 लाख करोड़ रुपये और गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह 8.94 लाख करोड़ रुपये शामिल है। ये आंकड़ा आयकर विभाग की राष्ट्रीय वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है, जो https://incometaxindia.gov.in/documents/d/guest/collection-data-as-on-10-11-2026-pdf इस प्रकार है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष करों से 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में प्राप्त 23.40 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 15 फीसदी अधिक है। सरकार अब तक इस लक्ष्य का करीब 53 फीसदी यानी 14.42 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है। ये आंकड़े 10 नवंबर तक के हैं।

सोनिया गांधी की किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पर्दा डालने की कोशिश : केवल सिंह ढिल्लों

चंडीगढ़। भाजपा पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोनिया गांधी की नई किताब में इंदिरा गांधी और 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर किए गए दावों को चुनौती देते हुए कहा कि यह 42 साल बाद गांधी परिवार और कांग्रेस के पापों पर पर्दा डालने की एक राजनीतिक चाल है। ढिल्लों ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की फुटेज देखकर इंदिरा गांधी की आंखों में 'दर्द और पछतावे के आंसू' आने का सोनिया गांधी का दावा सिख पंथ के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यदि पछतावा था, तो दशकों तक सच्चाई क्यों छिपाई गई? उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी स्वयं स्वीकार करती हैं कि पंजाब कांग्रेस के गुटों ने आपसी लड़ाई के लिए हालात बिगाड़े, लेकिन इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई को 'मजबूरी' बताकर परिवार और पार्टी को दोषमुक्त करने का प्रयास कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर टैंकों और तोपों से किए गए हमले तथा नवंबर, 1984 के सिख नरसंहार को केवल 'शर्मनाक अध्याय' कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। कांग्रेस के 'पंजाब मांगता है इंसाफ' अभियान और 'इंसाफ यात्रा' (साइकिल यात्रा) पर हमला बोलते हुए ढिल्लों ने कहा कि 1984 में हजारों निर्दोष सिखों के खून से रंगी कांग्रेस के मुंह से पंजाब में 'इंसाफ' की बात शोभा नहीं देती। उन्होंने सवाल किया कि 1984 के पीड़ितों को पूर्ण न्याय और कांग्रेस द्वारा अपने गुनाहों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे बिना पंजाब में 'इंसाफ यात्रा' का क्या अर्थ है?

उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने दोषियों को बचाया और उन्हें क्लीन चिट दी, जबकि 2014 के बाद मोदी सरकार द्वारा गठित एसआईटी के प्रयासों से ही सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजाएं हो सकीं और जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय हो सके। भाजपा अध्यक्ष ने मांग की कि गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व को किताबों और यात्राओं के नाटक के बजाय 1984 के पापों के लिए पंजाब और सिख पंथ से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए तथा न्याय में बाधा डालने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली पर्व है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों और सामने आई समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और तय समय-सीमा में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष गंगा महोत्सव 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर आयोजित होगा। चारों दिन सांस्कृतिक संध्या होगी। मुख्यमंत्री ने इसमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस बार सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने वाले रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें महिला स्वावलंबन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार दीपक भी शामिल किए गए हैं। दीप प्रज्वलन की व्यवस्था के लिए पूरे घाट क्षेत्र और रेतीले तट को सेक्टरों में बांटकर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देव दीपावली का



उल्लास केवल घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि समूची काशी में इसका प्रभाव दिखाई दे। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सारनाथ, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर और प्रमुख कुंडों पर भी दीपोत्सव के विशेष प्रबंध किए जाएं। 24 नवंबर को ही गुरु नानक जयंती होने के कारण गुरुद्वारों में लंगर, कीर्तन और संगत की व्यवस्थाएं भी समय से पूरी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नाविकों से संवाद कर उनका सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से प्रशिक्षण कराने की जरूरत पर बल दिया। अधिकारियों ने मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 24 नवंबर की शाम सभी घाटों पर दीप प्रज्वलित होंगे और दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चेत सिंह घाट पर भव्य प्रोजेक्शन एवं लेजर शो, दशाश्वमेध व अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो तथा काशी विश्वनाथ धाम घाट के सामने ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसके लिए पूरे घाट क्षेत्र को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में विभाजित कर जोनल व सेक्टर प्रभारियों की तैनाती की गई है। घाटों पर 27 वॉच टावर, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी), 21 प्रमुख घाटों पर एंटी-रोमियो स्क्वॉड, निजी गोताखोर और ड्रोन कैमरे तैनात रहेंगे।

जनवरी में कोलकाता में होगा 19वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन

कोलकाता। जनवरी महीने में कोलकाता में 19वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। न्यू टाउन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि कोलकाता में होने वाले इस सम्मेलन को यादगार बनाने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की है। उन्होंने कहा, 'मोदीजी का मंत्र है- कम बोलो, ज्यादा काम करो। हम इसे करके दिखाना चाहते हैं। पहली बार पश्चिम बंगाल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों के प्रवासी भारतीय कोलकाता पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन को इस तरह आयोजित करना है कि यहां से लौटने के बाद अतिथि कहें कि उन्हें सभी जगहों की तुलना में कोलकाता का अनुभव सबसे अच्छा लगा। तभी आयोजन सफल माना जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बुधवार को संक्षिप्त दौरे पर दिल्ली गए थे। वहीं उन्होंने सम्मेलन के पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को बंगाल आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि बंगाल आइए। दक्षिणेश्वर से लेकर कालीघाट तक के मंदिरों के दर्शन कीजिए। कोलकाता स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में पहली बार इस तरह का अंतरराष्ट्रीय आयोजन होने जा रहा है। राज्य में पहले ऐसा सम्मेलन आयोजित नहीं होने के कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती वाममोर्चा और तृणमूल कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 49 वर्षों तक बंगाल में केंद्र और राज्य में एक ही सरकार नहीं रही। इसके कारण इस तरह के आयोजन को लेकर कोई इच्छा भी दिखाई नहीं गई। जब भी किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कहा गया, उसे नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होना जरूरी नहीं है। हालांकि, पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन कोई दूरदृष्टि नहीं थी।

कोलकाता में इस सम्मेलन के आयोजन का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें इस कार्यक्रम के आयोजन का अवसर देने के लिए धन्यवाद। इस वर्ष हमने योग दिवस का आयोजन किया था, जिसमें सबसे अधिक लोगों ने भाग लिया था। हम इस सम्मेलन को भी सफल और यादगार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में इस तरह के आयोजन के लिए सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हैं।

लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए शुरू होगा इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट: अर्जुन राम मेघवाल

देवरिया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की दिशा में भी काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बुधवार को बरपार में पूर्व सांसद एवं पूर्व उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल स्व. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहर के रामनाथ देवरिया स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज मणि के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था में मुकदमों का लंबित होना एक बड़ी चुनौती है। उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक, देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख और जिला अदालतों, सीजेएम तथा जूनियर जजों की अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार लंबित मुकदमों का समय के आधार पर विश्लेषण शुरू किया है। यह पता लगाया जा रहा है कि कौन सा मुकदमा कितने वर्षों से लंबित है। 30 और 40 साल पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई में लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ मामलों में तो गवाहों का भी निधन हो चुका है, इसके बावजूद मुकदमे लंबित हैं। चेक बाउंस के



मामलों की संख्या भी काफी अधिक है। मेघवाल ने बताया कि न्यायिक व्यवस्था में नवाचार के तहत नियमित अदालतों के समय के बाद इवनिंग कोर्ट शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लाया जाएगा। शाम के समय भी तीन से चार घंटे अदालतें संचालित होंगी, जिससे लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ताओं को शाम का समय मुकदमों की तैयारी के लिए चाहिए, इसलिए इस व्यवस्था को लेकर उनका प्रतिरोध भी है। हालांकि नए अधिवक्ता इवनिंग कोर्ट में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का प्रावधान है। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तकनीक और एआई का इस्तेमाल करके मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास होगा। इस दौरान विधि विभाग के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी, विनायक मणि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कांत मिश्र, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र, त्रिपुरेश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का शानदार प्रदर्शन, लखनऊ देश के शीर्ष तीन स्वच्छ बड़े शहरों में शामिल

वाराणसी ने नदी तटीय नगरों में हासिल किया स्थान, गाजियाबाद बना प्रदेश का सबसे स्वच्छ नगर

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

लखनऊ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने नगरीय स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न शहरों को सम्मानित किया। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश के शहरों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम बताया।

मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ ने देश के तीन सबसे स्वच्छ बड़े शहरों में अपना स्थान बनाया है। वहीं धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी ने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ नदी तटीय नगरों में जगह हासिल की है। इसके अलावा गाजियाबाद प्रदेश के सबसे स्वच्छ नगर के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में बदलते नगरीय स्वरूप, बेहतर प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को दर्शाती हैं। प्रदेश के शहर अब स्वच्छता, सुंदरता और सुव्यवस्थित विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। श्री शर्मा ने इस सफलता का श्रेय सफाई मित्रों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और जागरूक नागरिकों को देते हुए कहा कि यह सम्मान उन सभी लोगों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जो शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को



जनआंदोलन का रूप दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, स्वच्छ सार्वजनिक स्थलों और आधुनिक नगरीय सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक नगर को स्वच्छता और सुव्यवस्थित विकास की मिसाल बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने सफाई मित्रों के योगदान की विशेष सराहना करते हुए कहा कि शहरों की स्वच्छता के पीछे उनका परिश्रम और सेवा भावना सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से इस उपलब्धि को बनाए रखने तथा भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सम्मान समारोह में लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव एवं निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जोरदार मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार

निवेशकों को एक दिन में 3.49 लाख करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार में आज भाईदूज के दिन जोरदार तेजी का माहौल बना रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई भारी गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ताबड़तोड़ खरीदारी के दम पर बाजार दिनभर हरे निशान में बना रहा। हालांकि, शुरुआती कारोबार में जोरदार तेजी हासिल करने के बाद ऊपरी स्तर पर मुनाफावसूली का हल्का दबाव भी देखने को मिला। इसके बावजूद बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में हुई चौतरफा लिवाली के सपोर्ट से सेंसेक्स और दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार हरे निशान में बने रहे। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.95 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ने 0.84 प्रतिशत की छलांग लगा कर आज के कारोबार का अंत किया।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 1,142.03 अंक यानी 1.41 प्रतिशत की शानदार छलांग लगा कर 82,248.68 अंक के स्तर पर खुला था। कारोबार की शुरुआत होते ही खरीदारों के जोर बनाने से यह सूचकांक 1,413.75 अंक यानी 1.74 प्रतिशत उछल कर 82,520.40 अंक के दिन के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद बाजार में मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण सेंसेक्स की चाल में गिरावट आने लगी। लगातार हो रही बिकवाली के दबाव की वजह से यह सूचकांक ऊपरी स्तर से 1,100 अंक से अधिक लुढ़क कर 81,417.39 अंक के निचले स्तर तक भी गया। राहत की बात यही रही कि बिकवाली का दबाव



बनने के बावजूद ये सूचकांक लगातार हरे निशान में ही बना रहा। पूरे दिन के उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स कुल 772.75 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की मजबूती के साथ 81,879.40 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की ही तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 ने भी आज जोरदार तेजी दर्ज की। निफ्टी 50 सूचकांक ने आज सुबह 25,337.80 अंक के स्तर से अपने कारोबार की शुरुआत की थी। शुरुआती सत्र की बंपर लिवाली के सपोर्ट से निफ्टी ने लंबे समय बाद 25,400 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार किया और 25,424.35 अंक के दिन के ऊपरी स्तर तक जा पहुंचा। हालांकि, अंतिम सत्र में हुई बिकवाली के कारण यह सूचकांक ऊपरी स्तर से थोड़ा नीचे फिसल गया। अंत में निफ्टी 50 सूचकांक कुल 210.40 अंक यानी 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,255.05 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

सेक्टोरल फ्रंट पर आज सरकारी बैंकों और ऑटोमोबाइल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक नजर आई। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.02 प्रतिशत की तूफानी तेजी के साथ सबसे आगे रहा, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स 2.29 प्रतिशत और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स 1.71 प्रतिशत मजबूत होकर बंद हुए। इसके अलावा ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स में भी 1 से 2 प्रतिशत तक की अच्छी बढ़त देखी गई। दूसरी ओर, फार्मा और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में आज बिकवाली का दबाव हावी रहा, जिसके चलते ये सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में आज दिनभर खरीदारी होती रही। लगातार हो रही लिवाली के सपोर्ट से निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.81 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 1.59 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 510.76 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 507.27 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 3.49 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिनभर के कारोबार के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एडवांस-डिक्लाइन आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजार में बढ़त का रुख पूरी तरह हावी था। आज के कारोबार में बीएसई में 4,712 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,913 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,592 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 207 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 3,346 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,315 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,031 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 20 शेयर बढ़त के साथ और 10 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 37 शेयर हरे निशान में और 13 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

अंताला इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को दिया करारा झटका, कमजोर लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

नई दिल्ली,एजेंसी। पैकेजिंग सेक्टर की कंपनी अंताला इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को जोरदार झटका दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 66 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 52.80 रुपये के स्तर पर हुई।

कमजोर लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयरों की चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये शेयर लगातार गिरता चला गया। लगातार हो रही बिकवाली के दबाव के कारण ये शेयर लुढ़क कर 50.16 रुपये के लोअर सर्किट लेवल पर पहुंच गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 15.84 रुपये यानी 24 प्रतिशत का नुकसान हो गया है। आईपीओ के तहत कंपनी ने लॉट साइज 2,000 शेयरों का तय किया था। इस तरह कंपनी के आईपीओ निवेशकों को आज इस शेयर की वजह से प्रति लॉट 31,680 रुपये तक की चपत लग गई। इस कंपनी का 22.98 करोड़ रुपये का आईपीओ 29 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 12.79 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 66.72 गुना (एक्स एंकर) सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 49.94 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 5.22 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 34.82 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। इस आईपीओ में नए शेयरों की बिक्री से जुटाई गई रकम में से 10.68 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके अलावा 5.89 करोड़ रुपये का उपयोग नई मशीनरी की खरीद और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद बची शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। अंताला इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वित्तीय स्थिति की बात करें, तो सेबी के पास जमा किए गए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी की वित्तीय सेहत में पिछले वित्त वर्षों के दौरान शानदार सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 89 लाख रुपये का शुद्ध लाभ (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) हुआ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 1.82 करोड़ रुपये हो गया और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 133 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 4.24 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की छमाही यानी 30 सितंबर तक कंपनी को 4.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था। इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 12.59 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (टोटल इनकम) प्राप्त हुआ था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 31.98 करोड़ रुपये हो गया और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 49 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 47.53 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 की छमाही यानी 30 सितंबर तक कंपनी को 30.20 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हो चुका था।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)